● वर्ष : 17 ● अंक : 165 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित | रविवार 05 अप्रैल 2026 | लोकतंत्र का स्तंभ

प्रधानमंत्री ने चेन्नई में भाजपा नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर किया मंथन

एजेंसी, चेन्नई

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में चेन्नई के गिंडी स्थित एक होटल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। भाजपा नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने चुनावी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय समिति के 18 सदस्यों के अलावा केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल, एल. मुरुगन, नैनार नागेंद्रन, के. अन्नामलाई, तमिलिसाई साउंडरराजन और वनाथी श्रीनिवासन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि चुनाव प्रचार को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जनसभाओं की संख्या बढ़ाई जाए और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि सशक्त रणनीति और आक्रामक प्रचार के जरिए पार्टी तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के बाद चेन्नई पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो कर भाजपा गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसंपर्क किया। इसके बाद वे चेन्नई लौटकर गिंडी स्थित होटल में ठहरे और आज उन्होंने यह बैठक की। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन में भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शुक्रवार को जारी 27 उम्मीदवारों की सूची में मायलापुर से तमिलिसाई सौंदरराजन, अविनाशी से एल. मुरुगन, कोयंबटूर उत्तर से वनाथी श्रीनिवासन, सत्तूर से नैनार नागेंद्रन और विलवन्कोडु से एस. विजयधारणी को मैदान में उतारा गया है।

प्रधानमंत्री की कूचबिहार में जनसभा कल, एसपीजी ने संभाला मोर्चा

एजेंसी, कूचबिहार । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा ऐतिहासिक रासमेला मैदान में आयोजित होगी, जिसे लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के अधिकारी कूचबिहार पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे है। वहीं, कूचबिहार एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी रविवार दोपहर करीब तीन बजे कूचबिहार एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए रासमेला मैदान स्थित सभा स्थल तक जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में संगीतकार रमेश विनायकम और परिवार के सदस्यों से की मुलाकात

एजेंसी, नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को संगीतकार, गायक और संगीत निर्देशक थिरु रमेश विनायकम और उनके परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मुझे थिरु रमेश विनायकम और उनके परिवार से मिलने का अवसर मिला। रमेश एक संगीतकार हैं और उन्होंने अपना जीवन भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने मुझे गमक बॉक्स नोटेशन सिस्टम बनाने के अपने काम की झलक दिखाई। भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर ले जाने का यह एक अभिनव तरीका है! उल्लेखनीय है कि चेन्नई के थिरु रमेश ने कर्नाटक और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया है।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होगा चुनाव आयोग?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनावों के पूर्व एसआईआर की प्रक्रिया पिछले कई माह से चल रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई भी चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से एसआईआर को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ रही हैं, दीदी चुनाव आयोग और भाजपा के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन गई हैं। चुनाव आयोग का एसआईआर का खेल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने समझ लिया है। फॉर्म नंबर 6 और 7 का जो खेल चुनाव आयोग में चल रहा है, उसे भी विपक्षी दलों और ममता बनर्जी ने पहचान लिया है।

जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में शीर्ष अधिकारियों से लेकर बीएलओ तक के ट्रांसफर किए हैं। इस मामले में ममता बनर्जी और उनके अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया है। न्याय पालिका में ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ने में कोई कोताही नहीं बरती। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को जो संवैधानिक संरक्षण और सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ममता दीदी को कोई लाभ नहीं मिला है। इसके बाद भी पूरी तरह से जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, एक धर्म विशेष के लोगों में जब हाईकोर्ट के जज का नाम भी कट गया, उसके बाद यह मामला जनता के बीच बड़ी तेजी के साथ पहुंच गया है। हाल ही में न्यायिक अधिकारी ब्लॉक ऑफिस में बैठकर जिन मतदाताओं के नाम नहीं जुड़े थे, उनकी शिकायतों पर जांच कर रहे थे। उन न्यायिक अधिकारियों को मतदाताओं ने कई घंटे तक बंधक बना कर रखा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पूरी रात जागकर प्रशासन को जागाना पड़ा।

उसके बाद बंधक जजों को बाहर निकाला जा सका। सुप्रीम कोर्ट को स्वंय संज्ञान लेकर आदेश करना पड़ा। सीआरपीएफ को न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाए। इस मामले में पहले ही टीएमसी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए यह कह दिया था। जिस बड़े पैमाने पर अधिकारियों के ट्रांसफर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिना राज्य सरकार के परामर्श के किए गए हैं, उसके बाद राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त प्रशासन काम कर रहा है। कानून व्यवस्था की पश्चिम बंगाल में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनकी संख्या लाखों में है। वह अपने नाम जुड़वाने के लिए आक्रोषित होकर स्थानीय अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

केरल में चुनाव प्रचार करने जा रहे शशि थरुर का काफिला रोका, गनमैन-ड्रायवर पर हमला

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम । केरल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का काफिला रोका गया और उनके गनमैन-ड्राइवर पर हमला किया गया है। घटना शुक्रवार रात 7.30 बजे मल्लपुरम के वांडुर में हुई। पुलिस के मुताबिक शशि थरूर जब चुनावी सभा के लिए जा रहे थे तब तिरुवल्ली में पांच लोगों ने उनका काफिला रोका। पुलिस ने बताया कि थरूर के गनमैन रतीश के पी ने इन लोगों को हटाने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। आरोपियों ने ड्राइवर पर भी हमला किया। मामले में एक आरोपी हिरासत में लिया गया है अन्य की तलाश जारी है। हमले में थरूर सुरक्षित हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक केरल के यंग वोटर्स 18 से 30 साल को 9 अप्रैल को वोटिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन तक 2 किमी के अंदर फ्री राइड मिलेगी। पहली बार वोट देने वाले वोटर्स को हलवा पैकेट मिलेगा। हर जिले में 200 पैकेट भेजे जाएंगे। वहीं तमिलनाडु के लालगुडी में चुनावी फ्लाइंग स्क्वॉड ने 50 लाख रुपए कैश जब्त किए, जिसका कोई वैध हिसाब नहीं दिया जा सका। यह रकम टीवीके उम्मीदवार कू पा कृष्णन के एक रिश्तेदार के घर से बरामद हुई है। टीवीके प्रमुख विजय के नामांकन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट के हलफनामे में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एक नए केस का जिक्र किया, जबकि पेरंबूर सीट के नामांकन में ये जानकारी नहीं दी थी। इस अंतर पर सवाल उठ रहे हैं और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तिरुनेलवेली में चुनाव प्रचार के दौरान रजनीकांत का गाना गाकर डीएमके का घोषणापत्र समझाया।

ईरान से भारतीयों को निकालने में मदद के लिए भारत ने आर्मेनिया का माना आभार

एजेंसी, नई दिल्ली । भारत ने शनिवार को ईरान से अपने नागरिकों को निकालने में मदद करने के लिए आर्मेनिया का आभार माना। आर्मेनिया के रास्ते कई भारतीय मछुआरों की ईरान से सुरक्षित वापसी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज ईरान से आर्मेनिया के रास्ते भारत में भारतीय मछुआरों को निकालने में मदद करने के लिए विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान और आर्मेनियाई सरकार को धन्यवाद। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात के बीच, हाल के दिनों में सैकड़ों भारतीय सीमा पार कर जमीनी रास्ते से आर्मेनिया पहुंचे। भारत अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित ट्रांजिट रूट सुनिश्चित करने के लिए इलाके की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, भारत ने मदद के लिए अजरबैजान को भी धन्यवाद दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि करीब 204 भारतीय नागरिक जमीनी सीमा चौकियों के रास्ते ईरान से अजरबैजान पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां कई भारत लौट चुके हैं, वहीं आगामी दिनों में और लोगों के आने की उम्मीद है।

बंगाल में अमित शाह के रोड़ शो के दौरान हुआ हंगामा, तीन एफआईआर दर्ज

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता रोड शो के दौरान हुए हंगामे को लेकर तीन एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के मौके पर आयोजित रोड शो का तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे कार्यक्रम अव्यवस्थित हुआ। दक्षिण कोलकाता के कालीघाट और हजरा सहित कई इलाकों में तनाव और नारेबाजी देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक, दो एफआईआर अलीपुर थाने में दर्ज हुई हैं। एक चुनाव आयोग की शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर और दूसरी स्वतः संज्ञान में लेकर दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक सख्ती दिखाकर एक संयुक्त बीडीओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के खंडाघोष क्षेत्र में तैनात संयुक्त बीडीओ ज्योत्सना खातून को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निर्वाचन आयोग ने कदम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर उठाया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र में स्पष्ट किया कि प्रस्ताव पर सहमति जताकर खातून के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति को "कमजोर" तो अन्य नेताओं ने संतुलित बताया

एजेंसी, नई दिल्ली

मीडिल ईस्ट में जारी तनाव और देश में इसके आर्थिक प्रभावों को लेकर कांग्रेस के अंदर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार की विदेश नीति को "कमजोर" बता रहे हैं, वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सरकार के रुख को संतुलित और जिम्मेदार बता रहे हैं। अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर राहुल गांधी ने सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे कमजोर बताते हुए अधिक स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाने की मांग की। इसके विपरीत, कांग्रेस सांसद शिश थरुर ने सरकार की नीति को "जिम्मेदार राजकाज" करार दिया। इसी तरह कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी संकेत दिया कि सरकार इस जटिल अंतरराष्ट्रीय स्थिति को सही तरीके से संभाल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया पर भारत की कूटनीतिक रणनीति को "परिपक्व और कुशल" बताया और राष्ट्रीय एकता की अपील की। घरेलू मुद्दों पर भी पार्टी के भीतर एकरूपता नजर नहीं आ रही है। एलपीजी संकट को लेकर जहां कांग्रेस नेतृत्व सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि "ऐसी कोई कमी नहीं है, बल्कि माहौल बनाया जा रहा है।" उनके इस बयान ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग रुख को उजागर किया है। इन बयानों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रम फैलाने और आंतरिक असहमति का आरोप लगाया।

विश्लेषकों का मानना है कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के अंदर ऐसे मतभेद सामने आए आ रहे हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सरकार के समर्थन में खड़े थे, जबकि राहुल गांधी ने आलोचनात्मक रुख अपनाया था। ताजा घटनाक्रम से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस के अंदर विदेश नीति और आर्थिक मुद्दों को लेकर एकमतता की कमी है। आने वाले समय में यह आंतरिक असहमति पार्टी की राजनीतिक रणनीति और चुनावी प्रदर्शन पर असर डाल सकती है।

ट्रंप ने दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ, भारत पर नहीं पड़ेगा सीधा असर

एजेंसी, नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रांडेड दवाओं और उनके घटकों (इनग्रेडिएंट्स) पर 100 फीसदी आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने के फैसले ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। ईरान के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ट्रंप के इस कड़े आर्थिक कदम को टैरिफ मिसाइल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, भारतीय दवा उद्योग के लिए राहत की खबर यह है कि इस भारी-भरकम टैक्स का भारत पर कोई सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति का असर केवल उन कंपनियों और देशों पर होगा जो ब्रांडेड दवाओं का निर्माण, खरीद और बिक्री करते हैं। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अनुसार, भारत को इस फैसले से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय दवा उद्योग की मजबूती जेनेरिक दवाओं में निहित है। भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है और अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए भारत से मुख्य रूप से इन्हीं किफायती दवाओं का आयात करता है। चूंकि ट्रंप का नया टैरिफ आदेश विशेष रूप से ब्रांडेड दवाओं और उनके कच्चे माल पर केंद्रित है, इसलिए भारत से होने वाले जेनेरिक दवाओं के निर्यात पर इसका असर नगण्य रहेगा।

सिलवासा में नाइट्रोजन गैस गोदाम में भीषण विस्फोट, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

एजेंसी, अहमदाबाद : दादरा नगर हवेली के सिलवासा में आज एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शहर के डैम के पास स्थित एक नाइट्रोजन गैस गोदाम में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास का इलाका कांप उठा। इस हादसे में गोदाम में काम कर रहे तीन मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गेस सिलेंडरों के टुकड़े दूर-दूर तक जाकर गिरे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गोदाम में विस्फोट हुआ, वह एक निजी स्कूल से मात्र 30 मीटर की दूरी पर स्थित था। हालांकि, सौभाग्य से विस्फोट की दिशा और तीव्रता स्कूल की ओर नहीं गई, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। अगर स्थिति थोड़ी भी अलग होती, तो कई मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, 08 लोगों की मौत

- रिक्टर स्केल पर 5.9 तीव्रता दर्ज, अफगानिस्तान के हिंदूकुश में केंद्र

एजेंसी, नई दिल्ली

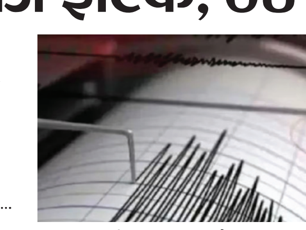

शुक्रवार रात दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में बताया जा रहा है, जहां इस प्राकृतिक आपदा में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में उस परिवार के सदस्य शामिल हैं, जिनकी मौत घर गिरने से हुई। भारत में भूकंप के कारण किसी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। हालांकि झटकों के कारण लोगों में दहशत का माहौल बन गया। रात करीब 9:46 बजे जैसे ही धरती कांपी, लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। कई जगहों पर इमारतों में लगे पंखे, झूमर और अन्य सामान हिलते हुए देखे गए। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। लोगों ने इस दौरान के कई वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिए, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पंजाब के पठानकोट स्थित भुल्ला चौक बाजार से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घर में लटकाए गए ताले झूलते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो स्थानीय निवासी अनमोल शर्मा द्वारा बनाया गया बताया जा रहा है। भूकंप के झटकों के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में हालात पर नजर रखी जा रही है, हालांकि अभी तक कहीं से भी जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, हिंदूकुश क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं और इनके झटके भारत के उत्तरी हिस्सों तक महसूस किए जाते हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग में 2 अमेरिकी विमान ढेर, एक जवान लापता

एजेंसी, तेहरान

ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध के पांचवें हफ्ते में प्रवेश करते ही ईरान ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अलग-अलग हमलों में अमेरिका के दो सैन्य विमानों को मार गिराया है। इस घटना ने पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन और जारी युद्ध की दिशा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, मार गिराए गए विमानों में से एक ईरान की सीमा के भीतर गिरा है। इस विमान में सवार एक अमेरिकी सैन्य कर्मी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि कम से कम एक अन्य सैनिक अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

ईरान के सरकारी तंत्र और वहां के मीडिया ने दावा किया है कि फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी ए-10 अटैक विमान को निशाना बनाया गया, जबकि एक अन्य दावे में एफ-15ई स्ट्राइक ईगल विमान को गिराने की बात कही गई है। एफ-15ई आमतौर पर दो चालक दल के सदस्यों—एक पायलट और एक हथियार विशेषज्ञ- के साथ उड़ान भरता है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी प्रसारित किए गए हैं, जिनमें पहाड़ी इलाकों के ऊपर अमेरिकी ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ते देखे जा सकते हैं। साथ ही, ईरानी मीडिया ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई विदेशी पायलट मिले, तो वे उसे तुरंत पुलिस के हवाले करें, जिसके लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। यह इस संघर्ष के दौरान पहला मौका है जब अमेरिकी विमानों को इस तरह के सीधे नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं।

हिंसा रोकने के लिए आयोग सख्त, पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां

एजेंसी, कोलकाता । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव नतीजे आने के बाद भी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियां राज्य में तैनात रहेंगी। यह तैनाती आयोग के अगले आदेश तक जारी रहेगी, ताकि मतगणना के बाद संभावित राजनीतिक हिंसा को पूरी तरह से रोका जा सके। प्रत्येक कंपनी में लगभग 80 से 100 जवान शामिल होते हैं, जो राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनावी प्रक्रिया को हिंसा, डर और प्रलोभन से मुक्त रखा जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के पिछले इतिहास को देखते हुए आयोग इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

खास खबर

शातिर स्नैचर को पुलिस ने दबोचा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने झपटमारी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाते हुए एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपित की गिरफ्तारी से पांच झपटमारी मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से 40 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपित की पहचान बबलू (40) निवासी मदनगीर, दिल्ली के रूप में हुई है। वह लंबे समय से पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर और मयूर विहार इलाके में झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पूर्वी जिला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती झपटमारी और चोरी की घटनाओं को देखते हुए स्पेशल स्टाफ को सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ का जिम्मा सौंपा गया था। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में गठित टीम ने स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए संदिग्धों पर नजर रखी। दो अप्रैल को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास नोएडा लिंक रोड पर जाल बिछाकर आरोपित को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 40 हजार रुपये नकद बरामद हुए। मौके से एक बाइक जब्त की गई, जबकि उसकी निशानदेही पर एक अन्य बाइक भी बरामद कर ली गई। जांच में बरामद नकदी का संबंध मयूर विहार थाने में दर्ज एक मामले से पाया गया है। आरोपित से पूछताछ में पांडव नगर और मयूर विहार के कुल पांच झपटमारी मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, आरोपित पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उससे पूछताछ जारी है और अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

पूर्वी दिल्ली में क्लब के बाहर चली गोली, युवक घायल

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में शनिवार तड़के एक क्लब के बाहर गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया। गोली लगने से 21 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार, 4 अप्रैल की सुबह करीब 4:33 बजे थाना प्रीत विहार को जीटीबी अस्पताल से एक युवक के गोली लगने की सूचना मिली। घायल की पहचान समीर (21) निवासी नूर-ए-इलाही, घोंडा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां समीर का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि समीर अपने दोस्तों के साथ प्रीत विहार स्थित एक क्लब में पार्टी करने गया था। इसी दौरान उसके दोस्त अरहम का वहां मौजूद कुछ अन्य युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष क्लब से बाहर सर्विस रोड पर आ गए। इसी दौरान पहले से बाहर मौजूद एक अज्ञात युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अचानक गोली चला दी, जो समीर के दाहिने पैर (घुटने के नीचे) में जा लगी। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। घायल समीर को उसके दोस्तों ने तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक ने पुलिस को बताया है कि वह हमलावर को पहचानता नहीं है। मौके पर क्राइम टीम ने निरीक्षण किया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की पहचान के प्रयास जारी हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है।

पंजाब की मान सरकार पर भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

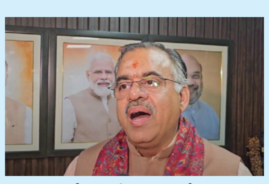

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव तरुण चुग ने पंजाब में आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके मंत्रियों ने वसूली के लिए घरों पर टॉर्चर सेंटर खोल रखे हैं। तरुण चुग ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि पंजाब में आआपा सरकार के मंत्रियों ने कथित तौर पर अपने घरों में यातना केंद्र स्थापित कर रखे हैं, जहां पीड़ितों को कथित तौर पर बुलाकर उनसे गंभीर दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि राज्य माफिया और गैंगस्टरों के वर्चस्व में है। सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक केंद्रों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने साबित कर दिया है कि उसे न कानून की परवाह है, न लोकतंत्र की। जो सरकार बाबा साहेब की प्रतिमा तक की रक्षा नहीं कर सकती, जो अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय विरोध की आवाज़ दबाने में लगी हो, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को जेल में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल किए किए पंजाब पुलिस ने अपराधी का मोबाइल अभी तक जब्त क्यों नहीं किया? अपराध में शामिल उनके पिता को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिन पर अत्याचार हुआ उनका बयान भी अगर पुलिस लेने जाती है तो उनकी बिजली काट दी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जावेद अहमद सिद्दीकी 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला के पास ब्लास्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को 17 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एडिशनल सेशंस जज शीतला चौधरी प्रधान ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में जावेद अहमद सिद्दीकी को 24 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 25 मार्च को इस मामले में सिद्दीकी को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। ये मामला दिल्ली के मदनपुर खादर गांव स्थित खसरा नंबर 792 में 1.14 एकड़ भूमि के विवाद से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक इस भूमि की कीमत 45 करोड़ रुपये है जबकि दस्तावेज पर इसकी कीमत 75 लाख अंकित है। जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को पहले मामले में गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला के पास ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थी। मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई। ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले मामले में ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

ईस्टर पर राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों, विशेषकर देश और विदेशों में रह रहे ईसाई समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईस्टर ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनः अवतरित होने की स्मृति में मनाया जाता है। यह पावन अवसर सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की कि वे इस अवसर पर आपसी सद्भाव, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लें और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर प्रयास करें।

'हिंदी थोपने' के एमके स्टालिन के आरोप निराधारः प्रधान

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर लगाए गए 'हिंदी थोपने' के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह राजनीतिक विफलताओं को छिपाने का प्रयास है। प्रधान ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषाई स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीति को 'अनिवार्य हिंदी' के रूप में पेश कर युवाओं के बहुभाषी बनने के अवसरों को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुभाषावाद किसी भाषा को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। केंद्र सरकार सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं एवं ढांचों के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पीएम-श्री स्कूलों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि पहले सहमति दी गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद नवोदय विद्यालयों की स्थापना में भी बाधाएं डाली जा रही हैं, जिससे गरीब और वंचित छात्रों को नुकसान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन राज्य सरकार की राजनीति के कारण प्रगति बाधित हो रही है। उन्होंने 'हिंदी थोपने' के मुद्दे को भ्रामक बताते हुए इसे अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया। इससे पहले स्टालिन ने एक्स पर आरोप लगाया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया पाठ्यक्रम ढांचा हिंदी को बढ़ावा देने और गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर थोपने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि तीन-भाषा फार्मूला वास्तव में हिंदी को दक्षिण भारत में लागू करने का माध्यम बन रहा है। स्टालिन ने सवाल उठाया कि क्या हिंदी भाषी राज्यों में तमिल, तेलुगु या अन्य भारतीय भाषाओं को अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने इसे एकतरफा और भेदभावपूर्ण नीति करार देते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे और भाषाई विविधता के खिलाफ है।

नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए दो नई वीड हार्वेस्टर मशीनों का जलावतरण

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शनिवार को पंजाबी बाग में नजफगढ़ ड्रेन की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दो नई वीड हार्वेस्टर मशीनों का जलावतरण किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह सिर्फ मशीनों का शुभारंभ नहीं है, बल्कि दिल्ली को जलभराव और गंदगी की समस्या से स्थायी समाधान देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रही है जो वर्षों तक जनता को राहत देगी और आज का यह जलावतरण उसी सोच का प्रतीक है। जब नालों की सफाई समय पर और आधुनिक तकनीक से होगी, तो जलभराव कम होगा, बीमारियां कम होंगी और जनता को सीधी राहत मिलेगी।इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलजीत सहारावत, विधायक कैलाश गंगवाल, निगम पार्षद सुमन त्यागी, जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बक्शी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सांसद सहारावत ने कहा कि इन अत्याधुनिक मशीनों के उपयोग से ड्रेन की सफाई प्रक्रिया में तेजी आएगी, जलभराव की समस्या में कमी आएगी तथा क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का असर, सभी मामलों की सुनवाई टली

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में शनिवार को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान का काफी असर देखने को मिला। आज उच्च न्यायालय में लिस्टेड करीब-करीब सभी मामलों में सुनवाई टल गई। मामलों से जुड़े मुख्य वकीलों के पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई। आज सुबह मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की बेंच समेत कई बेंच सुनवाई के लिए बैठी ही नहीं और मामलों की सुनवाई टाली गई। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच के समक्ष आज एक मामला लिस्ट हुआ था, जिसमें मुख्य वकील दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन हरिहरन को पेश होना था। जब जस्टिस भांभानी को बताया गया कि शनिवार की कोर्ट के न्यायिक बहिष्कार का फैसला किया गया है तो जस्टिस भांभानी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे उम्मीद थी कि हरिहरन पेश होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 अप्रैल को जारी नोटिस में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया था। नोटिस में बार एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से कहा गया था कि 4 अप्रैल से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने कहा था कि उच्च न्यायालय के प्रशासन को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन देकर अनुरोध किया गया कि शनिवार को न्यायिक कार्य अनिवार्य रुप से करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए लेकिन इस पर उच्च न्यायालय प्रशासन ने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया। बार एसोसिएशन ने कहा कि कार्यकारिणी को वकीलों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि शनिवार को कोर्ट के चलते रहने से व्यावहारिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इससे वकीलों का प्रोफेशनल शेड्यूल बिगड़ गया है। वकील विभिन्न ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और दिल्ली के बार के कोर्ट का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वकीलों को केस की तैयारी के लिए समय और मुवक्किल के साथ मीटिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुल मिलाकर वकीलों को अपने प्रोफेशनल दक्षता में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट न्यायिक कार्य करेगी। इसके पहले उच्च न्यायालय में कुछ अपवादों को छोड़कर शनिवार को न्यायिक कार्य नहीं होते थे यानि कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी।

खरगे बोले- राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा

» कहा- पुडुचेरी की एनआर-भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, 30 प्रतिशत कमीशन का राज चल रहा
» 'भाजपा-आरएसएस छोटे राज्यों के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं'

लोकतंत्र की शान , संवाददाता जीशान अली

नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सत्तारूढ़ एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन में 30 प्रतिशत कमीशन का शासन चल रहा है, सरकार भ्रष्टाचार के जरिए इस खूबसूरत जगह को लूट रही है और विकास ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस का वादा किया था, लेकिन जमीन से आसमान तक, एयरपोर्ट से पोर्ट तक, सब कुछ लूटा जा रहा है और एक व्यक्ति अडानी को सौंप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन जनता की जमीन और विरासत को लूट रहा है, जिसमें मंदिरों की जमीनें भी शामिल हैं। पूरे पुडुचेरी में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए खरगे ने कहा कि यह चुनाव पुडुचेरी की एकता, सद्भाव और प्रगतिशील सोच को बचाने का मौका है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस छोटे राज्यों के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं और पुडुचेरी में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के कारण चुनी हुई सरकार कमजोर हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासन में नारायणसामी के मुख्यमंत्री रहते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी सरकार के कामों में दखल देती थीं और फाइलें महीनों तक रोकी जाती थीं। खरगे ने जोर देकर कहा कि पुडुचेरी को पूरी शक्तियां दी जानी चाहिए और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। खरगे ने ड्रग माफिया और नशीले पदार्थों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि पूरी पीढ़ी नष्ट हो रही है और इसके लिए डबल इंजन सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने 450 नई शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट खोले हैं। जनता को साफ पानी देने के बजाय, यह सरकार छह नई शराब फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे रही है।

पश्चिम रेलवे में इंटरनेट और संचार सुधारने के लिए 398 करोड़ की परियोजना मंजूर

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद और रतलाम मंडलों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 398.36 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इस परियोजना के तहत रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई जाएगी, जिससे तेज और भरोसेमंद संचार नेटवर्क तैयार होगा। कुल 1929 किलोमीटर रूट पर यह केबल बिछाई जाएगी, जिसमें अहमदाबाद मंडल में 1456 किलोमीटर और रतलाम मंडल में 473 किलोमीटर शामिल हैं। रेलवे के अनुसार, इस काम से ट्रेनों के संचालन में इस्तेमाल होने वाले संचार सिस्टम और मजबूत होंगे। खासकर 'कवच' जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली को लागू करने में यह काफी मददगार साबित होगा, जिससे ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम भारतीय रेल को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना से रेलवे का कामकाज और तेज व सुरक्षित होगा। साथ ही यात्रियों को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी और माल ढुलाई में भी सुधार आएगा।

JIH लीडरशिप का कहना है, "वोटर्स को बांटने वाली राजनीति को खारिज किया जाना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करने और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर फोकस होना चाहिए"

» FCRA संशोधन बिल और SIR में हो रही अनियमिताओं पर चिंता जताई

लोकतंत्र की शान , संवाददाता जीशान अली

नई दिल्ली: जमाअते इस्लामी हिंद (JIH) के सर्वोच्च नेतृत्व ने अपनी मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले असेंबली चुनाव, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR), प्रस्तावित FCRA संशोधन बिल और ईरान के विरुद्ध जारी आक्रमण समेत चल रहे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आने वाले असेंबली चुनाव पर बोलते हुए, जमाअत के उपाध्यक्ष, प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने लोगों से सक्रिय और जिम्मेदारी से हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वोटिंग एक संवैधानिक अधिकार और नैतिक ज़िम्मेदारी दोनों है, और वोटरों से रोज़गार, शिक्षा, हेल्थकेयर और सामाजिक न्याय जैसे असली मुद्दों के आधार पर सोच-समझकर वोट करने की अपील की। उन्होंने वोटरों से विभाजित करने वाली ताकतों को नकारने और उन उम्मीदवारों का साथ देने की अपील की जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और सामाजिक मेलजोल के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से पैसे की ताकत, बाहुबल और विभाजित करने वाली बातों का दुरुपयोग न करने और यह सुनिश्चित करने की भी अपील की कि चुनाव अभियान लोगों की भलाई पर ही फोकस रहें। उन्होंने आज़ाद, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में देश के चुनाव आयोग की भूमिका पर ज़ोर दिया, और कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया को संभाला है, उसके बारे में हाल की अनियमिताओं और आरोपों ने उसपर लोगों का भरोसा कमज़ोर किया है और लोकतांत्रिक के लिए चुनौती खड़ी की है। उन्होंने चुनाव आयोग से सतर्कता और निष्पक्षता से काम करने और हेट स्पीच और लोगों को विभाजित करने वाले कैंपेन समेत मॉडल कोड के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने दोहराया कि आज़ाद, निष्पक्ष और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, नागरिक आज़ादी और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के साथ-साथ न्याय, शांति और स्थिरता के लिए ज़रूरी हैं, और सभी स्टेकहोल्डर्स से समाज के हित में ज़िम्मेदारी से काम करने की अपील की।

राघव चड्ढा का पलटवार-संसद में जनता के मुद्दे उठाने गया, हंगामा करने नहीं

लोकतंत्र की शान

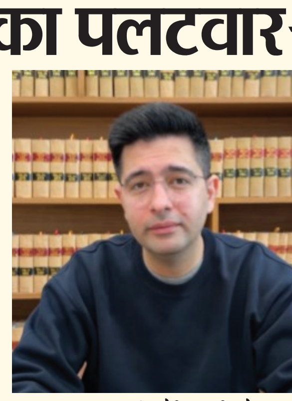

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) का अंदरूनी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने पार्टी नेताओं द्वारा उनपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह संसद में प्रभावी ढंग से जनता के मुद्दे उठाने गए हैं न कि हंगामा करने। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि 'उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। एक जैसी भाषा, एक जैसे आरोप। उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है, जो एक संगठित हमला है। आम आदमी पार्टी ने उन पर तीन आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह कि जब विपक्ष संसद से वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है। मैं चुनौती देता हूं कि एक भी उदाहरण दिखा दीजिए जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ न दिया हो।' उन्होंने कहा कि दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 'यह भी सफेद झूठ है। न तो किसी नेता ने उनसे इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने को कहा, न औपचारिक रूप से, न अनौपचारिक रूप से। पार्टी के 10 राज्यसभा सदस्यों में से 6-7 ने खुद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो दोष सिर्फ उन पर क्यों मढ़ा जा रहा है? इस प्रस्ताव के लिए कुल 50 हस्ताक्षर चाहिए थे, जो विपक्षी सांसदों की संख्या को देखते हुए आसानी से पूरे हो गए थे।' उन्होंने कहा कि तीसरा आरोप यह था कि वह डर गए हैं और बेकार मुद्दे उठाते हैं। 'मैं संसद में शोर मचाने, चीखने-चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। मैंने जीएसटी, इनकम टैक्स, पंजाब के पानी, दिल्ली की हवा, सरकारी स्कूलों की हालत, पब्लिक हेल्थ केयर, रेलवे यात्रियों की समस्याएं, यहां तक कि मासिक धर्म स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठाए हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर भी मैंने आवाज उठाई है। मेरा चार साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं संसद में इम्पैक्ट क्रिएट करने गया हूं, हंगामा करने नहीं।' दरअसल, इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 2 अप्रैल को आआपा ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया और उनकी जगह पार्टी सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल को उपनेता नियुक्त कर दिया। इसके बाद पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सदन में आआपा कोटे से राघव चड्ढा को बोलने का समय न दिया जाए। इसके जवाब में चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उन्हें जब भी संसद में बोलने का मौका मिलता है, वह जनता के मुद्दे उठाते हैं। 'क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? क्या उन्होंने कोई गलती की है? कोई उनके बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? उन्होंने हवाई अड्डों पर महंगे खाने, सामान पहुंचाने वाली कर्मचारियों की समस्याएं, खाने में मिलावट, टोल प्लाजा और बैंक चार्जेज की लूट, मध्यम वर्ग पर कर का बोझ, कंटेंट क्रिएटर्स पर कार्रवाई, संचार कंपनियों की मनमानी जैसे मुद्दे उठाए हैं।' राघव चड्ढा के इस वीडियो के बाद सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह जैसे आआपा नेताओं ने वीडियो जारी कर उनके खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया था। सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर कहा कि 'जो डर गया, समझो मर गया। राघव चड्ढा गंभीर मुद्दों पर चुप रहते हैं।' पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि 'अरविंद केजरीवाल के साथी निडरता से मोदी के खिलाफ लड़ते हैं। यही हमने उनसे सीखा है। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो राघव दस्तखत नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट छीने जा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, पंजाब के अधिकार छीने जा रहे हैं। इन सब पर वह खामोश रहते हैं।' आतिशी ने कहा कि 'राघव, भाजपा से इतने डरे हुए क्यों हैं? वह मोदी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन वह इस पर सवाल नहीं उठाते। जब विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाता है तो वह हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आम परिवारों के लिए संकट हैं लेकिन वह इस पर भी आवाज नहीं उठाते।'

नुमाइश में अव्यवस्था से अनहोनी की आशंका

लोकतंत्र की शान संवाददाता खिज्र अहमद / नजीबाबाद

नजीबाबाद(उतार प्रदेश) । नगर में चल रही नुमाइश इन दिनों अव्यवस्थाओं के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक ओर लोगों को मनोरंजन के लिए आयोजित होने पर नगर व आस-पास की जनता नुमाइश में भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के अधिकारीगण की लापरवाह व सुस्त होने के कारण लोगों की सेहत और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं जिससे क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य व जान का खतरा है। नुमाइश के आयोजन कर्ता नियम व मानको की खुले आम धज्जिया उड़ाते हुये यूवाओ को जुए की और बढ़ाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन मौन है। जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का शिक्षा को लेकर पूरी तरह जोर दिया जा रहा है वही नुमाइश के आयोजन कर्ता प्रशासन को ठेंगा दिखाकर अपनी मनमानी कर रहें। <आपको बता दे की नगर नजीबाबाद

क्षेत्र में लन्दन सिटी कार्निवाल के नाम से नुमाइश का आयोजन सरदार

कुल्वंत सिंह जमीन पर स्थित रायपुर रोड, नजीबाबाद में किया जा रहा है जिसका आयोजन मोहित जयसवाल, लुधियाना द्वारा किया जा रहा है। नुमाईश में लोगो के मनोरजंन के लिये कई स्टाले लगाई गई है जिसमें खाने-पीने के स्टाल, गेम के स्टाल, अन्य घरेलू समान की कई स्टॉल

कई फीट उच्चे झूले लगाये गये आदि है। नुमाईश के आयोजनकर्ता मोहित जयसाल द्वारा जो खाने-पीने की दुकाने लगाई गई है उनमें कोई भी गुणवत्ता का ध्यान नही रखा गया है और नाही साफ सफाई का ध्यान रखा गया जिसमें स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के

कारण नुमाइश करता मोहित लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर मोटी रकम कमा रहा हैं खाने पीने वस्तुओ की गन्दी और मखखी को बैठना आदि देखा जा सकता है जिससे फूड प्वाइजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उधर नमुमाईश में जनता के मनोरजन में कई फीट उच्चे झूले लगाये गये है जिसमें लोगो की सुरक्षा हेतु कोई भी व्यवस्था नही की गई। ऐसे में इन झूलों पर बैठने वाले लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं की जान जोखिम में पड़ सकती है। झूले/हिंडोले में कोई सुरक्षा लाक/उपकरण सीट बेल्ट, हार्नेस और लैप बार सहित सभी सुरक्षा उपकरण भी नही लगाये है जिसे प्रशासन द्वारा अंधेखा किया जा रहा है। सुत्रो का कहना है कि नुमाईश में आग लगने जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं हैं और ना ही कोई आपातकालीन रास्ते बनाये है जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। नुमाईश गेम का आयोजन किया गया जो कि जुअे का रूप है जो अवैध है और बिना किसी अनुमति के खुलेआम भोली भाली को लालच में डालकर जुआं चलाये जाकर लुटा जा रहा है और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौन बना हुआ है। नुमाइश में तेज आवाज में बज रहे म्यूजिक सिस्टम भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। आसपास के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं हृदय रोगियों और बुजुर्गों को भी इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनोरंजन कर, जी0एस0टी0, खाद्य विभाग द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है और नुमाईश में किसी भी वस्तु की खरीदारी व भुगतान किये जाने पर कोई बिल का भुगतान नही किया जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही हैं। प्रशासन को जल्द से जल्द इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और जांचोपारंत आयोजनकर्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे भविष्य में आयोजकर्ता नियम व नामकनुसार आयोजन करें जिससे आमजन को कोई हानि न हों। अब देखने यह है कि लन्दन सिटी कार्निवाल नुमाईश में हो रही लापरवाही को कौन देखेगा और स्थानीय प्रशासन की आंख कब खुलेगी ? क्या स्थानीय प्रशासन कोई अनहोनी होने की प्रतिक्षा में ? यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका स्थानीय प्रशासन में तैनात कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा

संक्षिप्त समाचार

बंदर से बचा तो हाई टेंशन लाइन से टकराया प्लंबर, घायल, हायर सेंटर रेफर

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः शनिवार को छत पर काम कर रहे प्लंबर पर अचानक बंदर ने हमला कर दिया बंदर के हमले से बचने के चक्कर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक शौचालय की छत से सड़क पर गिरकर घायल हो गया। गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है,नगर के मोहल्ला मनापुर निवासी तोताराम पुत्र ब्रह्मानंद पलंबर का कार्य करता है। शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे वह कोतवाली में काम करने के लिए आया था। कोतवाली के पीछे स्थित पुलिस की बैरक के बराबर में स्थित शौचालय की छत पर तोता राम काम कर रहा था। इसी बीच बंदर ने हमला कर दिया बंदर से बचने के चक्कर में अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से तोताराम टच हो गया तथा वह शौचालय की छत से सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। गनीमत रही की तोताराम हाई टेंशन लाइन से टच होकर दूर गिर पड़ा अन्यथा बड़ी घटना घटी हो सकती थी। बताया जा रहा है कि बंदर ने तोताराम पर हमला कर दिया था। जिससे वह बचने के चक्कर में हाई टेंशन लाइन के तारों से टच हो गया। कुछ देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल पलंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सको ने पलंबर को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाल राजेश कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पहुंच गये।

योगी सरकार की त्वरित कार्रवाई, सकुशल लौटा अखिलेश

लोकतंत्र की शान : अम्बेडकर नगर। इज़राइल के संघर्षग्रस्त नेटान्या शहर में फंसे अकबरपुर निवासी अखिलेश कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश व जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की पहल पर जॉर्डन के रास्ते सकुशल वापस लाया गया है। यह घटनाक्रम सीएम योगी के जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, जिला प्रशासन अम्बेडकर नगर की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं अंतरराष्ट्रीय समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अखिलेश कुमार इज़राइल में रोजगार हेतु गए थे, किन्तु वहां उनके नियोक्ता के असहयोग एवं युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव में आ गए और उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह स्वयं लौटने में असमर्थ हो गए। इस दौरान उनकी पत्नी किरण देवी, निवासी ग्राम हजपुरा, थाना सम्मनपुर, तहसील जलालपुर, ने 25 मार्च 2026 को आयोजित जनता दर्शन में उपस्थित होकर जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर अनुपम शुक्ला से मिलकर अपने पति की सुरक्षित वापसी हेतु भावनात्मक अपील की।

सरकार ने उच्चस्तरीय प्रयासों से कराई वापसी-प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा तत्काल इसकी जानकारी शासन को भेजी गई। मुख्यमंत्री के उच्चाधिकारियों को अखिलेश की सकुशल वापसी के निर्देश दिए। तब 28 मार्च 2026 को इज़राइल स्थित भारतीय दूतावास को इस संबंध में औपचारिक पत्र प्रेषित किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तेल अवीव स्थित भारतीय राजदूत, वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों, जॉर्डन स्थित भारतीय राजदूत एवं जॉर्डन प्रशासन से निरंतर उच्चस्तरीय समन्वय स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया। इज़राइल के हवाई अड्डों के बंद होने के कारण वैकल्पिक रणनीति के तहत 01 अप्रैल 2026 को जॉर्डन के वीज़ा एवं अंतरराष्ट्रीय एयर टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई तथा 02 अप्रैल 2026 को अखिलेश कुमार को विशेष वाहन से सुरक्षित तरीके से भारतीय दूतावास, तेल अवीव तक लाया गया, जहां से उन्हें स्थल मार्ग से सुरक्षित रूप से जॉर्डन सीमा तक पहुंचाया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वाराणसी के कंपोजिट विद्यालय शिवपुर वरुणापार जोन में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान : वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों समेत समाज के हर वर्ग का आह्वान किया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूटने न पाए। सीएम ने शिक्षा को सबसे पवित्र कार्य बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति के सामने बड़ा और यशस्वी बनने का अवसर आता है, जो उसके अनुरूप खुद को ढालता है वह यशस्वी बनता है। इसलिए हर बच्चे को स्कूल लेकर जाएं। बच्चा जब पढ़ लिखकर संस्कारी बनेगा तो कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब उससे मिलेंगे तो वह सम्मान देगा। जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जब बच्चा निरक्षर रह जाता है तो समाज निर्धन और प्रदेश-देश बीमारू बनता है। हमें हर बच्चे को शिक्षित करना है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना और विकसित भारत की दिशा में बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कंपोजिट विद्यालय शिवपुर वरुणापार जोन में शनिवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया, फिर बच्चों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी और स्कूल चलो अभियान की सार्थकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 9 वर्ष में लगभग 60 लाख नए बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूलों से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने परोसा मिड-डे मील बच्चों से कहा- रोज स्कूल आना

लोकतंत्र की शान

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ पर बच्चों को मिड-डे मील परोसा। उन्हें स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकों के साथ उपहार व चॉकलेट भी दी। सीएम ने निपुण विद्यालयों व बच्चों को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंचस्थ अतिथियों ने 'शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियां' पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान अभियान से जुड़ी लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

सीएम ने परोसा खाना, खिलखिलाए बच्चे- शिवपुर के कंपोजिट विद्यालय में 'स्कूल चलो' अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षारत बच्चों को मिड-डे मील परोसा। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से बच्चों को भोजन कराया तो बच्चों ने भी खिलखिलाकर सीएम के प्रति आभार प्रकट किया। जब मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि रोज स्कूल आना और मेहनत से पढ़ना, तो बच्चों ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। बच्चों ने मासूमियत से हाथ जोड़कर सीएम को अपना प्रणाम भी निवेदित किया। बच्चों को भोजन

परोसने में सीएम के साथ उनके मंत्री व जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे।

नए सत्र की पाठ्य पुस्तकों का वितरण -मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र की पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया। सीएम योगी के हाथों मंच पर कक्षा-1 के छात्र विकास, छात्रा अंशिका गुप्ता, कक्षा-2 की छात्रा श्रेया सोनकर, कक्षा-3 की छात्रा कजरी, कक्षा-4 की दीपशिखा, कक्षा-5 की रोली सोनकर, कक्षा-6 की श्रेया यादव, कली केसरी, कक्षा-7 की रूचि यादव, कक्षा-8 की साक्षी गुप्ता को स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकें, किट, उपहार व चॉकलेट मिली। इस दौरान बच्चों की सहज-सरल मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया।

अमरोहा में संपन्न हुआ पंचम श्री श्याम संकीर्तन, भक्ति के सागर में डूबे श्रद्धालु

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहा। श्री श्याम मित्र मण्डल सेवा ट्रस्ट (पंजी.) अतरासी कलाँ द्वारा आयोजित पंचम श्री श्याम संकीर्तन का भव्य कार्यक्रम शुक्रवार को हसनपुर रोड स्थित रुद्रा रिसॉर्ट में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर भारी संख्या में भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। मुख्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा की ज्योति के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया भजन संध्या और अमृत वर्षा शाम 6 बजे शुरू हुई इस संकीर्तन में सुप्रसिद्ध भजन गायकों शिवम रावल (इंदौर), अभिषेक नामा (जयपुर), साक्षी चोपड़ा (दिल्ली) और अश्वनी यादव ने अपनी मधुर वाणी से भक्तों को भावविभोर कर दिया। इससे पूर्व

प्रातः 11 बजे से अतरासी चामुण्डा मंदिर पर आयोजित विशाल भण्डारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।कार्यक्रम के सफल आयोजन में ट्रस्ट के निम्नलिखित पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहा।इस मौके पर कुशल चौधरी (विभाग सह-संयोजक, बजरंग दल) विपिन शर्मा (जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद) सुरजीत सिंह (बल उपासना प्रमुख) तेजेंद्र चौधरी (प्रखंड संयोजक),रवि कुमार (अध्यक्ष),गुरमीत कुमार (उपाध्यक्ष),आशु कुमार (कोषाध्यक्ष), चन्द्रशेखर (महासचिव),दीपक कुमार (सचिव) मौजूद रहे। अंत में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सेवादारों और नगरवासियों का आभार व्यक्त किया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत साइबर जागरूकता पर विशेष जोर, महिलाओं को सुरक्षित डिजिटल उपयोग के दिए गए टिप्स

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल/सिरसी थाना हजरत नगर गढ़ी में पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को साइबर जागरूकता के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया। थाना प्रभारी सुधीर पवार एवं उपनिरीक्षक रश्मि मलिक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने बताया कि आज के समय में ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, OTP फ्रॉड, फिशिंग लिंक, साइबर बुलिंग और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। महिलाओं को समझाया गया कि वे किसी भी अनजान

व्यक्ति के साथ अपनी बैंक डिटेल, OTP या पासवर्ड साझा न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग्स का उपयोग करने, मजबूत पासवर्ड रखने और अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने की भी सलाह दी गई। महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी प्रकार की ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेलिंग या धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि वे निडर होकर अपनी समस्या साझा करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता लें। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत चलाया जा रहा यह अभियान महिलाओं को न केवल सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, बल्कि उन्हें डिजिटल दुनिया में भी आत्मनिर्भर और सजग बना रहा है।

भगवान श्री परशुराम जयंती को लेकर मंदिर प्रबंध समिति की हुई बैठक

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहाः भगवान श्री परशुराम मंदिर प्रबंध समिति अमरोहा के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन शनिवार को समिति के अध्यक्ष पं० विजय चतुर्वेदी के आवास पर किया गया। जिसमे समीति के सभी सदस्यों ने आगामी 19 अप्रैल दिन रविवार को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम हेतु सभी ने अपने अपने विचार रखे।

महामंत्री कपिल शर्मा ने बताया की वासुदेव तीर्थ पर 19 अप्रैल को -भगवान परशुराम जी का जलाभिषेक - प्रातः 9 बजे,साज श्रृंगार - प्रातः 9:30 बजे,हवन - प्रातः 10 बजे,प्रसादी भोज- दोपहर 12 बजे होगा। बैठक में अध्यक्ष पं० विजय चतुर्वेदी, महामंत्री पं० कपिल शर्मा, कोषाध्यक्ष पं० सुशील शर्मा, अतुल पंडित, प्रतुल शर्मा, संजय भारद्वाज, सुभाष शर्मा, अरविंद श्रोत्रिय, पीयूष शर्मा, बासु दीक्षित सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

शहरी उपभोक्ताओं 25 दिन तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद गैस बुकिंग का आदेश भेदभावपूर्ण : शमशेर सैफी

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शनिवार को भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि के जिला अध्यक्ष शमशेर अली सैफी ने सरकार द्वारा गैस की किल्लत के चलते शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिन बाद गैस की बुकिंग करने तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद गैस की बुकिंग करने का आदेश के खिलाफ आवाज बुलंद की है , उन्होंने कहा कि सरकार का यह आदेश ग्रामीण तथा शहरी जनता में भेदभाव पूर्ण है सरकार से मांग करते हुए जिला अध्यक्ष शमशेर अली सैफी ने कहा है कि शहरी उपभोक्ताओं की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी 25 दिन बाद गैस बुकिंग का आदेश पारित किया जाए, उन्होंने बताया

कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी 95% लोग गैस पर ही आधारित हैं , वहीं उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा अवैध रूप से किताब विक्रेताओं तथा स्कूल यूनिफॉर्म विक्रेता द्वारा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की जेब पर डाले जा रहे डाके/ खुली लूट को बंद किए जाने को लेकर भी शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ।

निजी स्कूलों द्वारा किताबों के नाम पर की जा रही लूट के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शनिवार को तहसील क्षेत्र में निजी स्कूलों द्वारा पुस्तकों, यूनिफॉर्म और फीस के नाम पर की जा रही कथित 'अवैध वसूली' के खिलाफ तहसील परिसर में भारी रोष देखने को मिला। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन (बी आर अंबेडकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम हिमांशु उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंप कर कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी ने कहा कि क्षेत्र के निजी विद्यालय और चुनिंदा पुस्तक विक्रेताओं की मिलीभगत से अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य रूप से सस्ती एनसीआरटी पुस्तकों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें जबरन लागू की जा रही हैं। विद्यालयों द्वारा निर्धारित दुकानों से ही सामान खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जहाँ 50 से 60 प्रतिशत तक

अधिक कीमतें वसूली जाती हैं। हर साल बिना किसी शैक्षणिक कारण के किताबें बदल दी जाती हैं ताकि विद्यालय प्रबंधन को सीधा आर्थिक लाभ हो सके। विरोध करने पर छात्रों और अभिभावकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। यूनियन ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी स्कूलों पर FIR दर्ज की जाए और वसूली गई अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस दिलाई जाए। दिग्विजय भाटी ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन उग्र धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए विवश होगा।इस दौरान सोनू गुर्जर, कुलदीप भारती, मेवाराम खड़कवंशी, सूरजपाल, जफर राजा और अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

वैशाली में दो ट्रकों की टक्कर, एक की मौत, तीन घायल हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर, जांच जारी

हाजीपुर। वैशाली जिले के हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग पर सलहा चौक के पास शनिवार दोपहर दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना जंदाहा प्रखंड के चकुरदी गांव में दोपहर करीब 1:30 बजे हुई।

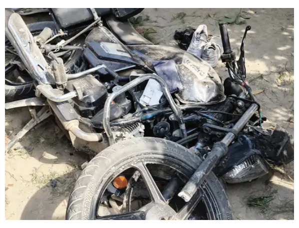

जंदाहा से हाजीपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर हुई इस टक्कर की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रक सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। दूसरा ट्रक उसके पिछले हिस्से में जा घुसा। हादसे में गौसपुर इजरा निवासी विश्वकर्मा कुमार (उम्र करीब 22 वर्ष), पिता सिंधेश्वर राय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत जंदाहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जंदाहा थाना प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है।

रेड करने गई पुलिस की वज्र गाड़ी खराब, शराब माफिया के खिलाफ होनी थी छापेमारी

हाजीपुर। वैशाली में शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस की वज्र वाहन खराब हो गई। महनार थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में यह घटना हुई, जहां पुलिस को वाहन को धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह कार्रवाई वैशाली पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर की जा रही थी। पुलिस टीम शराब कारोबारियों को पकड़ने और अवैध शराब के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए दियारा क्षेत्र में पहुंची थी। दियारा इलाका बड़े पैमाने पर देसी शराब के अवैध उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां शराब कारोबारी बड़े-बड़े भट्ठे लगाकर शराब बनाते हैं। पुलिस का उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना था।

वैशाली में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में महनार थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र में शराब माफिया बड़े पैमाने पर अवैध देसी शराब का निर्माण कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सभी अवैध शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर मौजूद करीब 1500 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। इसके साथ ही शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। हालांकि, पुलिस की गाड़ी को दूर से आता देख शराब माफिया मौके से फरार होने में सफल रहे। इस घटना के बाद वैशाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर वज्र वाहन के इस्तेमाल को लेकर। इस संबंध में पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वज्र वाहन का उपयोग मुख्य रूप से दंगा नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें आंसू गैस के गोले दागने की क्षमता होती है और इसका इस्तेमाल दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए किया जाता है।

सूखा नशा करने से रोका तो युवकों ने पीटा, पुलिस पर पीड़ित से रिश्वत लेने का आरोप, परिजन गाड़ी के सामने लेटे

हाजीपुर। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र में नशा सेवन रोकने पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने पीड़ित को ही पीटा, उससे एक हजार रुपये की रिश्वत ली और धमकी देकर छोड़ दिया। पुलिस के इस रवैये से नाराज परिजनों ने देर रात पुलिस का घेराव कर हंगामा किया। यह घटना देशराजपुर बजरंगबली चौक के पास बीते देर रात करीब 10 बजे हुई। 45 वर्षीय धर्मेंद्र राम (निवासी देशराजपुर बजरंगबली चौक, गणेश राम के पुत्र) ने कुछ लड़कों को सूखा नशा करने से रोका था। इसी बात पर लड़कों ने धर्मेंद्र राम की पिटाई कर दी। मारपीट के बाद धर्मेंद्र राम ने तत्काल डायल 112 पर महनार थाने की पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी लड़के भाग चुके थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय धर्मेंद्र राम को ही अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पीड़ित के अनुसार, पुलिस उसे अस्पताल ले जाकर इलाज कराने के बजाय करीब 5 किलोमीटर तक घुमाती रही। महनार स्टेशन के पास ले जाकर पुलिसकर्मियों ने धर्मेंद्र राम की पिटाई की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज भी की। धर्मेंद्र राम ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने उसे होश में रहने की चेतावनी दी और धमकी दी कि अगर उसने आगे से नशा करने वालों की सूचना दी तो उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। इसके बाद पुलिस ने उससे एक हजार रुपये की मांग की। धर्मेंद्र के पास नकद रुपये न होने पर, पुलिस ने स्टेशन स्थित दुकानदारों से यूपीआई ट्रांजेक्शन करवाकर नकद रुपये मंगवाए और रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। जब पुलिस धर्मेंद्र राम को घर छोड़ने आई, तो परिजनों ने पुलिस का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। परिवार के लोग पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए। थाना अध्यक्ष के घंटों मशक्कत के बाद मामला शांत हो सका।

सीएसपी लूटकर भाग रहे तीन अपराधियों को पकड़ा, 2 घंटे पहले 29,300 रुपए कैश लेकर भागे थे

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सीएसपी (CSP) से दिनदहाड़े लूट के तीन आरोपियों को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों ने बहिलबारा मलंग चौक स्थित ग्रामीण बैंक के सीएसपी केंद्र को निशाना बनाया था। पकड़े गए अपराधियों ने दोपहर 12.25 के आसपास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने करीब 2 बजकर 25 मिनट पर तीनों अपराधियों को सरैया थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, तीन नकाबपोश बदमाश एक बुलेट बाइक पर सवार होकर सीएसपी केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने हथियार के बल पर कर्मियों को बंधक बनाकर 29,300 नकद लूट लिए। लूट के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की और बुलेट से भाग निकले। लूट की सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने तत्काल घेराबंदी के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर सरैया कोतवाल और प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी प्रसन्ना वी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने वायरलेस पर सूचना मिलते ही अपराधियों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस से घिरता देख बुलेट सवार तीनों अपराधी अलग-अलग सड़क से कभी तुर्की थाना क्षेत्र तो कभी सरैया थाना क्षेत्र की ओर भागे। करीब 12 किलोमीमटर दूर पुलिस की टीम ने तीनों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटी गई 29,300 की रकम, वारदात में इस्तेमाल की गई बुलेट बाइक और हथियार बरामद किए गए हैं। लुटेरों ने सीएसपी संचालक धीरेंद्र कुमार को हथियार के बल पर धमकाया और नकदी व मोबाइल लेकर तुर्की की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जब दुकानदार सक्रिय हुए, तो बुलेट पर पीछे बैठे एक अपराधी ने हवा में एक गोली चलाई। अपराधी सरैया की ओर से आए थे। सीएसपी संचालक धीरेंद्र कुमार ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि मैं काउंटर पर बैठा था तभी बुलेट से तीन लोग उतरे। तीनों ने मेरी कनपटी पर बंदूक तान दी और धमकी देते हुए सारा पैसा और मेरा मोबाइल फोन छीन लिया। तीनों के चेहरे ढके हुए थे।

मनेर में मंत्री रामकृपाल के समधी के घर पर फायरिंग

जमीनी विवाद में दो पक्ष भिड़े, 15 राउंड चलाई गोली, तीन घायल

एजेंसी, पटना

पटना के मनेर थाना क्षेत्र के ब्यापुर में शुक्रवार देर शाम दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई। घटना बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर हुई, जहां करीब 15 राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। घटना रात 9 बजे के करीब की बताई जा रही है। इस घटना में समधी राजेंद्र सिंह के बेटे पप्पू, स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह के बेटे मनीष उर्फ गुड्डू और नितीश उर्फ बबलू घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मनीष और नितीश को इलाज के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया गया है, जबकि पप्पू को दानापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई है।

जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूपः जानकारी के अनुसार, रात करीब 9 बजे दो

गोतिया पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और फायरिंग शुरू हो गई। साथ ही तलवार, लाठी और पत्थरबाजी भी की गई।

करीब 15 राउंड चली गोलियांः परिजनों ने मुकेश, स्वर्गीय सतेंद्र के बेटे दीपक और प्रिंस सहित अन्य लोगों पर फायरिंग करने, तलवार, लाठी और रोड़ेबाजी से हमला करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 15 राउंड गोलियां चलाईं थी। मनेर थानाध्यक्ष रजनीश ने बताया कि शुक्रवार देर शाम आपसी विवाद में गोलीबारी और मारपीट की घटना संज्ञान में आई है, जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

छापेमारी जारी, जांच में जुटी पुलिसः मनेर थानाध्यक्ष रजनीश ने बताया कि, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे।' पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले की जांच जारी है।

पटना में 3 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म दो गिरफ्तार, तीसरा आरोपी फरार

एजेंसी, पटना

पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय चाचा पर अपनी तीन वर्षीय भतीजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस घटना में उसके दो दोस्त भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

मासूम के साथ गैंगरेप करने का आरोपः बच्ची के मां के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार देर रात की है। बच्ची का चाचा नशे का आदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची अपने घर में सो रही थी, तभी उसके चाचा ने उसे उठाया और घर से लगभग 500 मीटर दूर एक खेत में ले गया। वहां उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

चीखने चिल्लाने पर भागे तीनों आरोपीः बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों को लगा कि कोई बच्चा चोर घुस

♦ चाचा घर से उठाकर ले गया था खेत

आया है। जब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो तीनों युवक बच्ची को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस बीच बच्ची के परिवार के लोग भी बच्ची को खोजते हुए मौके पर पहुंच गए। खून से लथपत हालत में देख उन्होंने इसकी सूचना परसा बाजार थाने को दी।

पटना के एक अस्पताल में बच्ची को कराया भर्तीः सूचना पाकर परसा बाजार थाने की पुलिस ने आनन-फानन में मौके पर पहुंची। परिजनों और पुलिस टीम ने बच्ची को इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

गंगा में हाजीपुर के युवक की लाश मिली, गांधी सेतु से नदी में कूदा था

एजेंसी, पटना

गांधी सेतु पुल से गंगा नदी में कूदने वाले एक युवक का शव 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। SDRF की टीम ने हाजीपुर निवासी गुड्डू कुमार की लाश को पिलर नंबर-44 के पास से बरामद किया। गुड्डू कुमार शुक्रवार को हाजीपुर से पटना एक लाइब्रेरी में पढ़ने आया था। वह अपनी गाड़ी लाइब्रेरी में छोड़कर ऑटो से गांधी सेतु पहुंचा। परिजन से मोबाइल पर बात करते हुए उसने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी थी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे।

उन्होंने पटना सिटी के आलमगंज थाना और एसडीआरएफ टीम को जानकारी दी। सूचना के बाद आलमगंज थाने की पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 24 घंटे के अभियान के बाद एसडीआरएफ टीम ने गुड्डू कुमार के शव को गंगा नदी

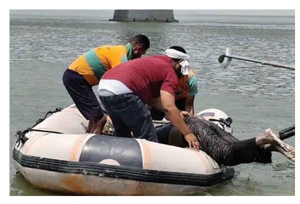

❒ 24 घंटे की छानबीन के बाद एसडीआरएफ ने निकाला शव

से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। गुड्डू कुमार के भाई रंजन कुमार ने बताया कि शुक्रवार को वह घर से नाश्ता करके लाइब्रेरी के लिए निकला था। उन्होंने बताया कि गुड्डु ने परिजन को फोन पर आत्महत्या की धमकी दी थी और फिर चप्पल उतारकर पुल से कूद गया। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि गुड्डु कुमार ने आत्महत्या क्यों की। इसके पीछे पारिवारिक विवाद है या फिर और कोई कारण है।

पटना में निशांत के 'फ्यूचर सीएम' पोस्टर से सियासी हलचल, नीतीश जगह पर सीएम बनने की मांग

एजेंसी, पटना

बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर "नए चेहरे" को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजधानी पटना के जदयू कार्यालय के पास जदयू कार्यकर्ताओं ने बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हैं। जिसमें नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार को प्रमुखता से दिखाते हुए उन्हें "Future CM of Bihar" के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। इस पोस्ट के जरिए जदयू कार्यकर्ता न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं बल्कि "विकसित बिहार-2040" का विजन भी सामने रखा गया है।

पोस्टर में क्या है खास?ः पोस्टर में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, वहीं दूसरी ओर निशांत कुमार को बड़े चेहरे के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ लिखा गया है— अब नए चेहरे पर, क्यूं करें विचार..." और

"जब 'क्लाइमेट लोड' के संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हैं भाई निशांत कुमार..." पोस्टर में यह भी दिखाया गया है कि "नीतीश सेवक" अब "मांग निशांत" की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कार्यकर्ताओं के बीच नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है।

जदयू के छात्र विंग ने लगाई पोस्टरः इस पोस्टर को छात्र जदयू, बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल ने लगाया है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह पहल पार्टी के अंदरूनी युवा या छात्र विंग से जुड़ी हो सकती है, जो नए नेतृत्व को आगे लाने की पैरवी कर रही है। इसके साथ ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तस्वीर भी लगाई गई है।

निशांत की लेकर जदयू

❒ लिखा-नए चेहरे पर क्यूं विचार..तैयार हैं निशांत कुमार

लगातार एक्टिवः नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री के साथ ही पार्टी की कमान उन्हें सौंपने और बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बिठाने की मांग लगातार तेज हो गई है। तमाम बड़े नेता यह कह रहे हैं कि निशांत की अगुवाई में ही पूरी पार्टी आगे बढ़ेगी। पटना की सड़कों में पोस्टर लगाकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बनाया जाए। हालांकि, सत्ता परिवर्तन को लेकर यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाएगी।

पटना हाई कोर्ट के वकील समेत 3 अरेस्ट

एजेंसी, पटना

राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक कथित हाईकोर्ट वकील और उसके दो सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों ने दफ्तर में बुलाकर युवक को बंधक बनाया, मारपीट की और न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। गिरफ्तार आरोपियों में कथित तौर पर चैतन्य कृष्ण, आलोक और मनीष शामिल हैं। चैतन्य कृष्ण, पटना के शास्त्री नगर इलाके में 'ऑर्थो लीगल सर्विसेज' नाम से दफ्तर चलाता था और मूल रूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।

आधार सुधार के नाम पर लिए 5 हजारः रोहतास के रहने वाले पीड़ित अजीत कुमार नाम के शख्स ने 3 अप्रैल को शास्त्री नगर थाने पर एक शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि उसने चैतन्य कृष्ण नाम के एक वकील से आधार कार्ड में सुधार के लिए बातचीत की थी। उसने भारत राजपत्र बनाने के नाम पर 5000 लिए थे, लेकिन बना नहीं रहा था। 2 अप्रैल की रात में अजीत ने चैतन्य कृष्ण को फोन करके बातचीत करने की कोशिश की। फोन करते ही चैतन्य कृष्ण ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया।

वीडियो बनाने पर बंधक बनाकर पीटाः

इसके बाद 3 अप्रैल को अजीत अपने दोस्त पंकज के साथ वकील चैतन्य कृष्ण से मिलने उसके दफ्तर गए। दफ्तर में पहले से मौजूद चैतन्य कृष्ण, आलोक और मनीष ने उनसे अभद्रता शुरू कर दी। इस पर पीड़ित अजीत ने पंकज को मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के लिए कहा। जैसे ही पंकज ने वीडियो बनाना शुरू किया, चैतन्य कृष्ण आलोक और मनीष ने मोबाइल फोन छीन लिए। फिर तलवार भिड़ाकर बंधक बना लिया। 2 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट करते रहे और चप्पल जूते से मारते रहे।

न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोपः पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान चैतन्य कृष्ण और उसके साहगिर्द ने दोनों के कपड़े उतरवा दिए और सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रयास किया। खुद चैतन्य भी नशे का सेवन कर रहा

♦ दफ्तर में बंधक बनाने, न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप, छापेमारी में मिले करीब 100 फर्जी मोहर

था। इस दौरान पंकज और अजीत को भी नशे का सेवन करने के लिए फोर्स कर रहा था। पीड़ित ने मोबाइल फोन लौटाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उसने 10000 की डिमांड कर दी। किसी तरह 7000 देकर मोबाइल फोन वापस लौटाया गया। आरोप है कि इस दौरान उनके कपड़े उतरवाकर न्यूड फोटो और वीडियो बनाए गए। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर इन्हें वायरल करने की धमकी दी गई।

दरभंगा के घनश्याम को भी दिया झांसाः शनिवार के दिन अर्थव लीगल सर्विसेज के बाहर आधार में गलत नाम सुधार कराने के लिए दूर दराज से लोग आए थे। उनमें से इंतजार कर रहे दरभंगा के घनश्याम ने बताया कि, 'नाम सुधरवाने के लिए आए थे। यहां पर आने के बाद पता चला कि पारिवारिक कलह में वकील चैतन्य कृष्ण थाने गए हैं। आज केंद्र नहीं खुलेगा। घनश्याम से नाम सुधरवाने के नाम पर 3000 की डिमांड की गई थी। इन्हें बताया गया था कि वकील चैतन्य कृष्ण का दिल्ली से संपर्क है। सीधे नाम में सुधार करा देते हैं।

बिहार में मौसम का डबल अटैक, पारा 40° पार

एजेंसी, पटना

बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और खराब मौसम का दोहरा असर देखने को मिलेगा। एक ओर जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचकर लू जैसे हालात बना रहा है। वहीं, दूसरी ओर 6 अप्रैल को कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों को गर्मी और मौसम की मार, दोनों से सतर्क रहने की जरूरत है।

गर्मी का कहरः रोहतास सबसे गर्मः पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे बिहार में तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में गर्मी ने सबसे ज्यादा असर दिखाया है। रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 40.0°C दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। गया में 39.8°C, पटना में 39.4°C और

शेखपुरा में 39.9°C तापमान रिकॉर्ड किया गया। लगभग सभी जिलों में तापमान 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, तेज धूप और पश्चिमी हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक लू जैसे हालात बने रह सकते हैं, खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है।

पटना का 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमानः राजधानी पटना के लिए मौसम मिला-जुला रहने वाला है— गर्मी के साथ बीच-बीच में राहत भी मिलेगी। जहां आज दिन में गर्मी रहेगी, लेकिन रात में गरज के साथ हल्की बारिश या छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान 38°C रहेगा।

बुडको बनाएगा मॉर्डन लैब, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच होगी सख्त

एजेंसी, पटना

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के लैब की स्थापना की जाएगी। यह जानकारी प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने दी। उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ़ वर्क को बढ़ाने के लिए एक लैब की जरूरत महसूस हो रही थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स सहित अन्य निर्माण कार्यों के जांच के लिए ये लैब मददगार साबित होगी। इस लैब की मदद से हमलोग गुणवत्तापूर्ण कार्य को डिलीवर कर सकेंगे। दरअसल आज बुडको द्वारा 'मिशन प्रोजेक्ट कम्पलीशन' प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

यह एक तीन दिवसीय प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के दौरान जलापूर्ति, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, सड़क निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना और अमृत योजना पर चर्चा की जाएगी। इन योजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम

का आयोजन किया गया। मिशन प्रोजेक्ट कम्पलीशन के प्रथम चरण में प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर के निर्देशन में सभी जिलों का निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों और अभियंताओं की टीम ने डिटेल स्थल जांच की और रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी थी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 38 जिलों से परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक और अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें प्रत्येक जिले के पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति, अब तक की प्रगति और सामने आ रही बाधाओं और समाधान को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे।

पटना में कांग्रेस का नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम छूटे प्रतिभागियों का हो रहा इंटरव्यू

एजेंसी, पटना

बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब बिहार में अपने आप को मजबूत करने में लगी है। पटना में शनिवार को रिजनल लेवल पर नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसका लक्ष्य जमीनी स्तर से ऐसे सक्षम व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और सशक्त बनाना है, जो जिला-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें। इसमें समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर दिया गया है। आज इंटरव्यू-पैनल डिस्कशन होगा।

करंट अफेयर्स, पार्टी की विचारधारा से जुड़े पूछे जा रहे सवालः प्रोग्राम के कन्वेनर

असित नाथ तिवारी ने कहा कि ऐसे लोग जो अपने जोन में आयोजित इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाए थे या किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं दे पाए थे। उनके लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम पटना में रखा गया है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को मौका देना है जो पार्टी के विचारधारा के साथ खड़े होना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई लिंक है या रास्ता नहीं मिल पाता है। इसलिए उन जैसे लोगों को किसी सिफारिश के बिना कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है। बस वह अपनी योग्यता दिखा कर इसमें शामिल हो सकते हैं। इस दौरान आवेदन करने वाले लोगों से पार्टी की विचारधारा से जुड़े सवाल, करंट अफेयर्स, भारत-बिहार के इतिहास, सामान्य ज्ञान और जिस विषय में पढ़ाई किए हो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

तीन पदों पर हो रही टैलेंट हंट में खोजः इस पहल के अंतर्गत

❒ करंट अफेयर्स-पार्टी की विचारधारा से जुड़े पूछे जा रहे सवाल

कांग्रेस पार्टी तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभाओं की खोज कर रही है। पहला मीडिया प्रवक्ता-पैनलिस्ट जो टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक मंचों पर स्पष्टता, विश्वसनीयता और अनुशासन के साथ पार्टी का पक्ष रख सकें। दूसरा रिसर्च को-ऑर्डिनेटर जो तथ्य-आधारित, शोध-आधारित सामग्री, नीतिगत विश्लेषण और मुद्दा-ब्रीफ तैयार कर पार्टी के संदेश को मजबूती दें। तीसरा पब्लिसिटी को-ऑर्डिनेटर जो सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप नेटवर्क, स्थानीय मीडिया और जमीनी स्तर पर पार्टी का संदेश व्यापक रूप से पहुंचाए।

संक्षिप्त समाचार

हरियाणा में शुरू होंगी ग्रुप डी की भर्तियां

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। हरियाणा में जल्द ही ग्रुप डी की भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। इन पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पदों को छोड़कर बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों तथा सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं में ग्रुप-डी के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर अपने-अपने विभागों और संबद्ध संस्थाओं में ग्रुप-डी के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में 10 अप्रैल, 2026 तक आवश्यक जानकारी मुहैया कराएं। मांगी गई जानकारी में स्वीकृत पदों की संख्या, नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद, अनुबंध कर्मचारियों, खास तौर से हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत आने वाले कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद तथा शेष रिक्त पदों की कुल संख्या शामिल है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा तक जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती को 15 अप्रैल से शुरू होगा पीएमटी

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पीएमटी की परीक्षा हेतु युवाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्रदेश में 15 अप्रैल से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) शुरू होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। आयोग चेयरमैन ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब इंतजार खत्म, पीएमटी 15 अप्रैल 2026 से आयोजित किया जाना संभावित है। पीएमटी के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा में करीब ढाई लाख युवा भाग लेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। खेल विभाग के सहयोग से पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बॉस्केटबाल और वॉलीबाल हॉल को आरक्षित किया गया है। वहीं लंबे टेस्ट शेड्यूल के लिए ड्यूटी देने को खेल विभाग से कोच भी मांगे हैं।उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में पुलिस सिपाही भर्ती निकाली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5,500 पदों पर पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले 5061 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती हुई थी। वर्तमान में 4500 पुरुष कांस्टेबल और 600 महिला कांस्टेबलों भर्ती किए जाएंगे। इस भर्ती में करीब 2.70 लाख अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म को कंप्लीट सबमिट किया है।

रेवाड़ी में गैस सिलेंडर से भरी एजेंसी की गाड़ी से चोरी, 6 सिलेंडर गायब

हाईवे किनारे होटल पार्किंग में सो रहे चालक के दौरान वारदात, धारूहेड़ा थाना पुलिस ने दर्ज किया केस

लोकतंत्र की शान : रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खड़ी गैस एजेंसी की गाड़ी से सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने देर रात गाड़ी का ताला तोड़कर छह गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद धारूहेड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में भिवानी जिले के गांव अमीरवास निवासी राजेश ने बताया कि वह लोहारू स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी पर चालक है। वह भारत पेट्रोलियम के प्याला बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) प्लांट से 306 गैस सिलेंडर लेकर भिवानी के लिए निकला था। शुक्रवार शाम को वह प्लांट से रवाना हुआ। इस दौरान रास्ते में वह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर राव व संगम होटल के पास स्थित पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर उसी में सो गया। देर रात होटल कर्मचारियों को कुछ संदिग्ध गतिविधि नजर आई, जिसके बाद उन्होंने चालक को सूचित किया। चालक ने जब गाड़ी की जांच की तो ताला टूटा हुआ मिला और छह गैस सिलेंडर गायब थे। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजेश ने बताया कि कंपनी के नियमों के अनुसार रात 11 बजे के बाद भरे सिलेंडरों के साथ सड़क पर सफर नहीं किया जाता, इसलिए उसने निर्धारित समय से पहले सुरक्षित स्थान पर गाड़ी खड़ी कर दी थी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

ऑपरेशन चक्रव्यूह : 20 किलो अवैध डोडा पोस्त का वांछित पांच हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : जोधपुर। कमिश्नरेट पुलिस जिला पश्चिम की तरफ से इन दिनों मादक पदार्थ तस्करों एवं अवैध हथियारों के प्रकरण में वांछित चल रहे अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ चल रही है। इसी कड़ी में जिला पश्चिम पुलिस ने अब पांच हजार के इनामी अपराधी को पकड़ा है, जोकि मादक पदार्थ तस्करी में वांटेड था। प्रकरण में तीन आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पांच हजार के इनामी अभियुक्त फींच लूणी निवासी सुभाष पुत्र हाउराम को गिरफ्तार किया गया है। वह चार महिने से फरार था। वह बालोतरा जिले के समदड़ी एवं कुड़ी भगतासनी थाना जोधपुर में वांटेड था। प्रकरण संबंध में तीन अभियुक्तों भागीरथ पुत्र पप्पाराम, गणपतलाल पुत्र भारताराम एवं भागीरथ पुत्र जालाराम को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। आरोपितों के खिलाफ 20.185 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त का केस दर्ज है। अभियुक्त सुभाष की गिरफ्तारी के लिए लूणी थाने की एएसआई प्रेमराज, हैडकांस्टेबल गणपतलाल एवं महिला कांस्टेबल विमला को लगाया गया था।

परीक्षा सील्ड बॉक्स की फोटो स्टेट्स पर लगाना पड़ा भारी, कर्मचारी सस्पेंड

लोकतंत्र की शान : जोधपुर। जोधपुर में आयोजित उप निरीक्षक/ प्लाटून कमाण्डर संयुक्त परीक्षा 2025 के सील्ड बंद स्टील बॉक्स के फोटो खींचकर स्टेट्स पर लगाना सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ गया। सरकारी कर्मचारी दीपक को विभाग की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। इसके खिलाफ उदयमंदिर थाने में शिक्षा विभाग की तरफ से परिवाद भी दिया गया है। उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि 03 अप्रैल को उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर संयुक्त परीक्षा 2025 की सील्ड बंद स्टील बॉक्स को कोषालय में रखते हुए सरकारी कार्मिक दीपक गहलोत ने उसे फोटो खींच ली। बाद में उसे अपने मोबाइल के स्टेट्स पर लगा दिया। इसका पता लगने पर उसे विभाग की तरफ से निलंबित करने के आदेश जारी हो गए। वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसोप भोपालगढ़ में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक लगा हुआ है।उसने कौतूहलवश फोटो खींच कर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, जिसकी सुचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से उक्त कार्मिक से पूछताछ की गई जिससे उसने अज्ञानतावश स्टेट्स लगाना जाहिर किया गया। कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया तथा फोटो खींचने के सम्बन्ध में दिया गया परिवाद पर जांच की जा रही है।

जमीन से जुडे कलेक्टर ने जमीन पर बैठकर सुनी फरियाद

कलेक्टर के प्रति लोंगों मे दिख रहा भरोषा व विश्वास

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय की रिपोर्ट)

सीधी। अल्प समय में ही जिले के बहुचर्चित नवागत कलेक्टर विकास मिश्रा की कार्यशैली ने आम लोगों में भरोसा पैदा कर दिया है, शिविर में जाने से अब उनके समस्या का समाधान भी होगा जो जमीन में बैठकर लोगों के आवेदनों को गंभीरता से पढ़ समझ कर निदान के लिए मौके पर संबंधितों को निर्देशित किया जाता है। या यू कहा जाए की जमीन से जुड़े कलेक्टर जमीन में बैठकर लोगों की फरियाद को जमीनी स्तर पर निदान करने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रभावित व पीड़ित लोगों के लिए बरदान साबित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर की इस कार्यशैली का नजारा ग्राम पंचायत बोदारी टोला में 4 अप्रैल को आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में दिखा जहां ग्रामीणों के आवेदनों को कड़ी धूप में जमीन में ही उनके साथ बैठकर प्रत्येक आवेदन को निराकरण के लिए संबंधित विभाग को दिया गया एवं आवेदकों को यह भरोसा दिलाया गया कि अगर एक माह के अंदर उनके आवेदन पर निराकरण नहीं होता है तो वह खुद निराकरण करेंगे।

दिव्यांग बच्चों को लेकर पहुंचा पिता

ग्राम ताला निवासी एक व्यक्ति अपने 12 वर्षीय दिव्यांग बेटे को गोद में उठाकर कलेक्टर के पास पहुंचा एवं बताया कि 8 माह से उसका निराश्रित पेंशन एवं खाद्यान्न बंद है जिस पर कलेक्टर ने सम्बंधित विभाग के अधिकारीयों से कारण पूँछ उन्हें लताड़ लगाई व उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे समस्या का जल्द ही निदान हो जाएगा। कलेक्टर के आश्वासन पर पीड़ित पिता भाबुक होकर रोने लगा जिसे जिला कलेक्टर ढाढस बधाकर शांत किया वहीं जनपद सीईओ को आदेशित किया है कि अपने वाहन से आधार केंद्र भेज कर इसका तत्काल आधार कार्ड में सुधार कराया जाए ताकि इसे योजना का लाभ मिले। इसी तरह ही कई अन्य समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए जिससे लोगों में भरोसा जगा कि उनके समस्या का निदान होगा वहीं कलेक्टर की कार्यशैली से जहां आम नागरिक खुश नजर आए और उनमें भरोसा जगा वहीं प्रशासन तंत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों में दहशत का माहौल भी देखा गया।

ट्रैक्टर मामले में नया मोड़: पुलिस पर प्रक्रिया में चूक, दोहरी FIR और कोर्ट आदेशों की अवहेलना के गंभीर आरोप पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट जाने की कही बात

लोकतंत्र की शान

बैतूलः रामकिशोर पवार बैतूल जिले के भैंसदेही में ट्रैक्टर मामले को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में मोनिका विजायकऱ (पत्नी राजेश विजायकऱ) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भैंसदेही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने बिना तथ्यों की पूरी जांच और वेरिफिकेशन किए रिपोर्टिंग की, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाई। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि राजेश विजायकऱ ने ट्रैक्टर रिकवरी में पुलिस का पूरा सहयोग किया था और उनकी सक्रिय भूमिका भी रही। इसके बावजूद पुलिस उन्हें एक पुराने मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, जो आठनेर थाने में करीब डेढ़ साल से लंबित है। आरोप है कि इस मामले की जांच पूरी होने और फाइनल रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी उसी प्रकरण में दोबारा FIR दर्ज कर दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। मोनिका विजायकऱ ने यह भी कहा कि कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिससे यह मामला और संदिग्ध हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जांच पूरी हो चुकी है तो चार्जशीट अब तक क्यों नहीं पेश की गई? साथ ही, एक ही घटना में दूसरी FIR दर्ज करना सुप्रीम कोर्ट के "टेस्ट ऑफ सेमनेस" सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है।

हितग्राहियों का खाद्यान्न डकारने वाले दो विक्रेताओं पर गिरी कार्यवाही की गाज

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय की रिपोर्ट)

सीधी। जिला कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा मझौली ब्लाक में उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया जहां विक्रेताओं की शिकायते प्राप्त हुई थी जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिया गया था। मामले पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मझौली के द्वारा प्रारंभिक जांच की गई जिस पर नारों एवं देवरी दुकान के विक्रेताओ द्वारा वितरण प्रणाली पर लापरवाही करना पाये जाने पर प्रथम दृष्टिया दोषी पाया गया।जिसका प्रतिवेदन के आधार पर सीईओ सहकारिता के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान नारों के विक्रेता वीर बहादुर सिंह पिता बांकेलाल सिंह को खाद्यान वितरण प्रणाली से हटाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान गिजवार के विक्रेता अमृत लाल गौतम पिता रोहित प्रसाद गौतम को नारों दुकान का प्रभार आगामी आदेश तक के लिये सौंपा गया है। इसी तरह शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी के विक्रेता सुरेश प्रसाद शुक्ला को भी वितरण प्रणाली से हटाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान ठोगा के विक्रेता धर्मेंद्र तिवारी को देवरी दुकान का प्रभार सौंपा गया है। दोनों विक्रेताओं के खिलाफ जांच की कार्यवाही अभी की जा रही है।

इनका कहना है। मामले में प्रारंभिक जांच के दोषी मानते हुए कार्यवाही की गई है जांच की जा रही है। गणेश चन्द्रवंशी, सीईओ सहकारिता मझौली।

छात्रों को बंटने आई किताबें खंडहर में तब्दील

» बाजार से खरीदनी पड़ रहीं छात्रों को पुस्तकें

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय की रिपोर्ट)

सीधी। जिले के रामपुर नैकिन में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बच्चों को मुफ्त बांटने के लिए आई सैकड़ों सरकारी किताबें एक पुरानी जर्जर इमारत में सड़ती हुई मिली हैं। हैरानी की बात यह है कि यह इमारत जनपद शिक्षा केंद्र दफ्तर के बिल्कुल बगल में है। नमी और गंदगी की वजह से इन किताबों की हालत बहुत खराब हो चुकी है और अब ये पढ़ने लायक नहीं बची हैं। जिस जगह ये किताबें रखी थीं, वहां मवेशी भी घूमते रहते हैं, जिससे किताबों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में गांव के रहने वाले प्रशांत सिंह ने बताया कि ये किताबें करीब दो साल पहले बच्चों को बांटने के लिए आई थीं। लेकिन न तो इन्हें बच्चों तक पहुंचाया गया और न ही वापस विभाग को भेजा गया। इस लापरवाही का खामियाजा गरीब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें मजबूरी में बाजार से महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं।

जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी

इस बारे में बीआरसी रामपुर नैकिन के प्रभारी श्रीप्रकाश जायसवाल से बात की गई, तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि यह उनका काम नहीं है और वे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे की जानकारी के लिए बीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की सलाह दी।

बिना ई-टोकन के उर्वरक विक्रय करने पर 24 फर्मों के उर्वरक लाइसेंस किए निलंबित

लोकतंत्र की शान

बैतूलः रामकिशोर पवार , जिला कलेक्टर बैतूल ने जिला मुख्यालय की 3 नामचीन खाद विक्रेता के लाइसेंस निलंबित कर दिये। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई खण्डेलवाल परिवार की फर्म परमानंद चंद्रगोपाल खंडेलवाल बडोरा, पीसी खंडेलवाल बैतूल गंज,सहित एक अन्य पर कार्रवाई करके यह संदेश देने का काम किया है कि कानून की नजर में सब एक समान है। म.प्र. शासन कृषि विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों में अप्रैल 2026 से खाद का वितरण अब ई-विकास प्रणाली के तहत ई-टोकन के माध्यम से ही खाद का वितरण प्रारंभ किया गया है। बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा लगातार ई विकास प्रणाली से खाद वितरण की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। ई विकास प्रणाली से ही खाद वितरण के सख्त निर्देश के बावजूद भी 01 अप्रैल 2026 के बाद कतिपय समितियों द्वारा बिना ई-टोकन से खाद वितरण किया जाना पाया गया है। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा तत्काल विषय को संज्ञान में लिया जाकर ऐसी समितियों के कर्मचारीयों / अधिकारीयों पर तत्काल दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए। जिसके पालन में ऐसी 03 समतियों अंधारिया, सोनेगांव एवं डंगारिया के प्रबंधकों को निलंबित किया गया तथा 01 प्रभारी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने का नोटिस दिया गया। साथ ही जिले के सभी कृषकों से आग्रह किया गया हुआ शत् प्रतिशत ई-विकास पार्टल पर ई-टोकन के माध्यम से ही खाद प्राप्त करें , ताकि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में किसानों को लाभन्वित किया जा सके।

24 फर्मों के उर्वरक लाइसेंस किए निलंबित-किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक डॉ.आनंद कुमार बडोनिया ने बताया कि 3 अप्रैल को आईएफएमएस पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 24 खुदरा विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर कुल 94.359 मीट्रिक उर्वरक विक्रय किये जाने पर उक्त फर्मों के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये है। उप संचालक कृषि डॉ. बडोनिया ने बताया कि शासन के आदेश की अवहेलना किये जाने के फलस्वनरूप कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (1) तथा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 के तहत उक्त कार्यवाही की गगई है। उर्वरक वितरण, विक्रय पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

इन फर्मों के लाइसेंस किए निलंबित-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्राथमिक सहाकारी समिति अंधारिया, सोनेगांव, डंगरिया निजी विक्रेता में परमानंद चंद्रगोपाल खंडेलवाल बडोरा, पीसी खंडेलवाल बैतूल गंज, हरीदास किराना स्टोर चोपना, विक्की ट्रडर्स डोढरामउ,अन्नपूर्णा ट्रेडर्स आमडोह चोपना, रावत कृषि सेवा केन्द्र ढूमुर, कमलप्रसाद दिनानाथ साहू खेडलीबाजार, वासू खाद भंडार बोरदेही, गोपी साहू कृषि सेवा केन्द्र रतेडाकला, सुमित खाद विक्रय केन्द्र मालेगांव, सूर्यवंशी कृषि सेवा केन्द्र जमदेही कला, वैष्णवी कृषि सेवा केन्द्र मुलताई, दिव्यांशु खाद भंडार बोरदेही, पंकज कृषि सेवा केन्द्र चिचोली, गायत्री कृषि सेवा केन्द्र चिचोली, तेजस कृषि सेवा केन्द्र खेडीकोर्ट, दीक्षा कृषि सेवा केन्द्र गोहाची, जय गुरूदेव कृषि सेवा केन्द्र सोहागपुर, मार्का एफपीसी लिमि. शीतलझिरी, कृषि सेवा केन्द्र खेडलीबाजार, मां यमुना कृषि सेवा केन्द्र मोही के लाइसेंस में लंबित किए गए है।

भाजपा जिला कार्यालय का भूमि पूजन 6 अप्रैल को, पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय की रिपोर्ट)

सीधी। दिनांक 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 09:30 बजे हॉस्पिटल चौक, न्यू भारत होटल के बगल में भाजपा जिला कार्यालय के भूमि पूजन का कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में आयोजित होगा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने बताया कि पार्टी के भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कर कमलों द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता में एवं संभाग संगठन प्रभारी विजय दुबे, लोकसभा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिला संगठन प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवकुमार सिंह चौहान, सीधी विधायक श्रीमती रीती पाठक, धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक, पूर्व विधायक चुरहट शरदेंदु तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू राम सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न होने जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने बताया कि पार्टी के भूमि पूजन कार्यक्रम में कार्यक्रम को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे जिले से पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सैकड़ो की संख्या में सक्रिय सदस्य भाग लेंगे।

रेत की अवैध निकासी पर गरमाई सियासत, शिवसेना नेता का बड़ा बयान

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय की रिपोर्ट)

सीधी। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने रेत की अवैध निकासी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो रेत खनन को केवल अपराध के रूप में देखना उचित नहीं है। विवेक पांडे ने सोन नदी का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वहां अवैध रेत खनन हो रहा है, तो यह बढ़ती बेरोजगारी का संकेत है। उनके अनुसार, युवा रोजगार के अभाव में ऐसे कार्यों की ओर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में घड़ियाल संरक्षित हैं, वहां प्रतिबंध जारी रहना चाहिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में रेत निकासी की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि खदानों को जल्द स्वीकृति दी जाए, ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। पांडे ने सीधी जिला का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां से बड़े पैमाने पर रेत अन्य राज्यों में भेजी जाती है, लेकिन स्थानीय जनता को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने यह भी कहा कि रेत खनन को जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया गया है।

हथनीकुंड बैराज डायाफ्राम वॉल में जंग लगे सरिये के उपयोग के आरोप

लोकतंत्र की शान

यमुनानगर। यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही 146 करोड़ रुपये की डायाफ्राम वॉल के निर्माण में जंग लगे सरिये के उपयोग के आरोप लगे हैं, जिससे परियोजना की गुणवत्ता और बैराज की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। समाचार एंजेसी को प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बैराज को संरचनात्मक नुकसान पहुंचा है। समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण इसका बेस स्तर काफी नीचे चला गया, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोखिमपूर्ण माना गया। इसके बाद हरियाणा सिंचाई विभाग ने मामले को केंद्रीय स्तर पर उठाया, जिस पर सेंट्रल वॉटर कमिशन की टीम ने निरीक्षण कर डिजाइन और तकनीकी मानक निर्धारित किए। निर्धारित योजना के तहत डायाफ्राम वॉल का निर्माण कार्य पिछले वर्ष शुरू हुआ था, जिसे जून तक पूरा किया जाना था। हालांकि संसाधनों की कमी और अन्य कारणों से कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। बाद में इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन अब तक लगभग 70 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। अब इसे मानसून से पूर्व मई तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच निर्माण स्थल पर रखे सरिये में जंग लगने और उसी सामग्री के उपयोग के आरोप सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे निर्माण में उच्च गुणवत्ता और जंग-रोधी सरिये का इस्तेमाल अनिवार्य होता है, विशेषकर उन हिस्सों में जो पानी और जमीन के भीतर रहते हैं। वहीं, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर तकनीकी स्टाफ तथा परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परियोजना की संवेदनशीलता को देखते हुए इसके निर्माण की गुणवत्ता पर प्रशासन और विशेषज्ञों की निगरानी अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई, तो यह परियोजना भविष्य में बड़े जानमाल के जोखिम का कारण बन सकती है।

संक्षिप्त समाचार

जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे ट्रम्प के बेटे, ड्रोन बनाने वाली कंपनी से जुड़े

नई दिल्ली। अमेरिका में एक ड्रोन स्टार्टअप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्प के बेटे एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जुड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लोरिडा की पावरस कंपनी मिडिल ईस्ट के देशों को अपने ड्रोन सिस्टम बेचने की कोशिश कर रही है। ट्रम्प के बेटे एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर फरवरी के अंत में इस कंपनी से सलाहकार के तौर पर जुड़े थे, ये वही समय था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। हालांकि दोनों को कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। पावरस से जुड़े अधिकारियों ने अबू धाबी में अधिकारियों से मुलाकात की है। बातचीत इस बात पर हुई कि UAE को हथियार और ड्रोन डिफेंस सिस्टम बेचे जा सकते हैं, क्योंकि वह ईरान के खिलाफ अपने डिफेंस को और मजबूत करना चाहता है।

इस घटना के बाद आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति के परिवार के लोग युद्ध से फायदा कमा रहे हैं। पावरस के सह-संस्थापक ब्रेट वेलिकोविच ने बताया कि उनकी टीम खाड़ी के कई देशों में ड्रोन डेमो दिखा रही है, ताकि यह समझाया जा सके कि उनके इंटरसेप्टर ड्रोन ईरानी हमलों से बचाव में कैसे मदद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन देशों में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वेलिकोविच ने कहा कि अमेरिका को चीन और रूस जैसे देशों से मुकाबले के लिए तेजी से ड्रोन तकनीक विकसित करनी होगी, नहीं तो वह पीछे रह जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस पूरे मामले से यह साफ होता है कि ईरान युद्ध के चलते ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम की मांग बढ़ रही है। ईरान सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी महंगे मिसाइल सिस्टम से उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। इससे लागत का बड़ा अंतर पैदा हो रहा है। यही वजह है कि सस्ते और असरदार एंटी-ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा मौका बन रहा है। पावरस ने हाल ही में 'गार्डियन-1' नाम का एक इंटरसेप्टर लॉन्च किया है, जो खास तौर पर आत्मघाती ड्रोन, जैसे ईरान के शाहेद-136 को गिराने के लिए बनाया गया है।

23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान। ईरान जंग के एक महीने बाद ट्रम्प ने 2 अप्रैल को अमेरिकी जनता को संबोधित किया। 19 मिनट के भाषण में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की हवाई सेना को तबाह कर दिया है और उनके पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर कब्जा हो चुका है। उनके विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं और ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ऐसे ही दावे किए। लेकिन हालात अब अलग कहानी बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के दो सैन्य विमान और सर्च ऑपरेशन में लगे दो ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर ईरान के हमले का शिकार हुए। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, 23 साल में पहली बार अमेरिकी लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में गिराए गए। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। ईरानी मीडिया के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया गया। यह ईरान के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में उड़ान भर रहा था। F-15E फाइटर जेट के क्रू को ढूंढने के लिए अमेरिकी विमान A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ। A-10 हमले के बाद कुवैत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां पायलट ने सुरक्षित तरीके से इजेक्ट किया। पायलट सुरक्षित है, हालांकि विमान कुवैत में क्रैश हो गया। CBS के अनुसार, F-15E में दो क्रू मेंबर थे। इनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि दूसरा लापता है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि पैराशूट के जरिए बाहर निकला यह क्रू सदस्य देश के दक्षिणी हिस्से में उतरने का अनुमान है। वहीं, F-15E फाइटर जेट के रेस्क्यू के लिए 2 ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर भेजे गए थे। उन पर भी हमला हुआ। हालांकि, इन पर मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कटौती, नया भाव 378 रुपये प्रति लीटर

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। यह एक महीने तक लागू रहेगी। यह कटौती पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये प्रति लीटर की कमी के बाद की गई है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में सरकार ने राष्ट्रीय संसाधनों से 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी है। इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ जनता पर पड़ने से रोकना है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित सब्सिडी की भी घोषणा की है। मोटरसाइकिल चालकों को 100 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। परिवहन क्षेत्र को भी राहत उपायों में शामिल किया गया है। बढ़ते परिचालन खर्चों की भरपाई के लिए मालवाहक और कमर्शियल वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन बसों को हर महीने 100,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, ताकि यात्रियों के लिए किराया स्थिर रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी-क्लास ट्रेन यात्रा का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।

जज पर एडिशनल सेशन जज के घर चोरी के आरोप, पटियाला में सिविल जज के खिलाफ 7 महीने बाद एफआईआर

लुधियाना। पंजाब के पटियाला में सिविल जज पर एडिशनल सेशन जज के घर में चोरी करने के आरोप लगे हैं। सिविल जज के खिलाफ घटना के सात महीने बाद 21 मार्च को FIR दर्ज की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए सिविल जज द्वारा लगाई गई बेल भी कोर्ट ने रद्द कर दी। एडिशनल सेशन जज हरिंदर सिद्धू ने आरोपों को गंभीर मानते हुए सिविल जज की बेल को रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक मृतक सहकर्मी के आवास से संदिग्ध परिस्थितियों में भारी मात्रा में सोना और अभूषण निकालना गंभीर आरोप है। पटियाला के एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की एक अगस्त 2025 को अस्पताल में मौत हो गई थी। सिविल जज विक्रमदीप और अन्य लोगों पर आरोप है कि उसी दिन रात को उन्होंने एडिशनल सेशन जज के घर से सोना व आभूषण चोरी किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने नोट किया कि विक्रमदीप और मृतक के बेटे अंगदपाल सिंह के बीच वाट्सऐप चैट और कॉल रात 10:15 बजे के बाद की है, जबकि CCTV फुटेज रात 9:50 बजे तक के हैं। इससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि सामान मृतक के बेटे से संपर्क करने से पहले ही हटा लिया गया था। सिविल जज व उसके सहयोगियों के खिलाफ मृतक एडिशनल सेशन जज के दोस्त व पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ भूपिंदर सिंह विर्क की शिकायत पर 21 मार्च को FIR दर्ज हुई। उनके बेटे ने इस केस को प्रोसीड करने के लिए डॉ भूपिंदर सिंह विर्क को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है।

हाल के कई वैश्विक झटकों ने हमारी लचीलेपन की परीक्षा ली

एजेंसी, रायपुर

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "हम अब दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हाल के कई वैश्विक झटकों ने हमारी लचीलेपन की परीक्षा ली है और भारत उससे मजबूती से बाहर निकला है। हमने घरेलू और बाहरी दोनों चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है।" विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर शनिवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) नया रायपुर स्थित परिसर में 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों के 552 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिनमें प्रमुख एमबीए प्रोग्राम के 314, एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के 230 और 8 डॉक्टरेट शोधार्थी शामिल थे। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया।

♦ भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर का 15वां वार्षिक दीक्षांत समारोह

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा, "स्नातक होने वाले इस बैच को खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। क्योंकि यह उस पीढ़ी का हिस्सा है जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियत है। आप एक दशक की ठोस प्रगति और विकास के लाभार्थी हैं। आपको तकनीक और सूचना तक वह पहुंच प्राप्त हुई है, जिसकी कल्पना एक पीढ़ी पहले करना भी असंभव था। यही नहीं आप वैश्वीकरण के उस युग में बड़े हुए हैं, जिसने आपको शेष विश्व के साथ बहुत गहराई से जोड़ा है। आज भारत अपनी विकास यात्रा में एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और आपका यह समूह उन लोगों में शामिल होगा जो इस प्रयास का नेतृत्व करेंगे। आपके कौशल हमारे राष्ट्र को समृद्धि की खोज में आगे ले जाने में मदद करेंगे।"

विदेश मंत्री ने कहा, "यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि आज भारत में स्नातक होने वालों की संभावनाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक उज्ज्वल हैं। वास्तव में, हमारे समाज में एक ऐसा आशावाद है जो दुनिया के कई अन्य हिस्सों में नहीं दिखता। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? शायद इसलिए, क्योंकि पिछले दस वर्ष बहुत बेहतर रहे हैं, जिससे यह विश्वास पैदा हुआ है कि अगले दस वर्ष और उसके बाद का समय भी वैसा ही होगा। आखिर हम अब दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हाल के कई वैश्विक झटकों ने हमारी लचीलेपन की परीक्षा ली है और भारत उससे मजबूती से बाहर निकला है। हमने घरेलू और बाहरी दोनों चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है।" आईआईएम रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष पुनीत डालमिया ने कहा, "2026 के बैच, आप गहरे वैश्विक बदलाव के क्षण में स्नातक हो रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल व्यवधान, भू-राजनीतिक बदलाव और तेजी से बदलते उपभोक्ता व्यवहार वाले युग में जी रहे हैं। ऐसी दुनिया में ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुकूलन क्षमता अनिवार्य है।

राघव चड्ढा का पलटवार-संसद में जनता के मुद्दे उठाने गया, हंगामा करने नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आआपा) का अंदरूनी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने पार्टी नेताओं द्वारा उनपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह संसद में प्रभावी ढंग से जनता के मुद्दे उठाने गए हैं न कि हंगामा करने।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि 'उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। एक जैसी भाषा, एक जैसे आरोप। उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है, जो एक संगठित हमला है। आम आदमी पार्टी ने उन पर तीन आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह कि जब विपक्ष संसद से वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं।

इस पर उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है। मैं चुनौती देता हूं कि एक भी उदाहरण दिखा दीजिए जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ न दिया हो।' उन्होंने कहा कि दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 'यह भी सफेद झूठ है। न तो किसी नेता ने उनसे इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने को कहा, न औपचारिक रूप से, न अनौपचारिक रूप से। पार्टी के 10 राज्यसभा सदस्यों में से 6-7 ने खुद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो दोष सिर्फ उन पर क्यों मढ़ा जा रहा है? इस प्रस्ताव के लिए कुल 50 हस्ताक्षर चाहिए थे, जो विपक्षी सांसदों की संख्या को देखते हुए आसानी से पूरे हो गए थे।'

उन्होंने कहा कि तीसरा आरोप यह था कि वह डर गए हैं और बेकार मुद्दे उठाते हैं। 'मैं संसद में शोर मचाने, चीखने-चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। मैंने जीएसटी, इनकम टैक्स, पंजाब के पानी, दिल्ली की हवा, सरकारी स्कूलों की हालत, पब्लिक हेल्थ केयर, रेलवे यात्रियों की समस्याएं, यहां तक कि मासिक धर्म स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठाए हैं।

बीआईआरएसी-बायोनेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर की शुरुआत रिसर्च आधारित स्टार्टअप्स को देगा नई दिशा

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मैसूर में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी)- बायोनेस्' इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस पहल से देश में रिसर्च को बाजार से जोड़ने की दिशा में मदद मिलेगी। यह अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन सेंटर फूड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है, जहां उन्हें आधुनिक लैब, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध को व्यावसायिक उत्पादों में बदलना और स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण से लेकर बाजार तक पहुंचने में मदद करना है।

कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से बातचीत करते हुए कहा कि आज के दौर में स्टार्टअप शुरू करना पहले की तुलना में आसान हो गया है, लेकिन उसे लंबे समय तक बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिसर्च संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच मजबूत तालमेल जरूरी है, ताकि नवाचार को बाजार की जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके। उन्होंने रेडी-टू-ईट और कंवीनियंस फूड जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं को भी रेखांकित किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मार्च 2026 तक इस बायोनेस्ट सुविधा के तहत 26 स्टार्टअप्स को सहायता दी जा चुकी है। जिनमें कई फिजिकल और हाइब्रिड इन्क्यूबेट्स शामिल हैं। इन स्टार्टअप्स ने मिलकर 12 पेटेंट दाखिल किए हैं और कई उत्पाद बाजार में लॉन्च किए जा चुके हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि भारत में फूड और बायोटेक सेक्टर तेजी से नवाचार की ओर बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि फूड सेक्टर अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर हाई-वैल्यू और साइंस-ड्रिवन क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रहा है।

इस मौके पर चार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और दो नए उत्पाद भी लॉन्च किए गए। साथ ही, सीएफटीआरआई के 75 साल पूरे होने पर विशेष प्रकाशन और स्मारक सामग्री भी जारी की गई।

बलोचिस्तान में पाकिस्तान सुरक्षा बलों के 86 जवान मारे गए, बीएलए ने लिया जिम्मा

एजेंसी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में आजादी की मांग को लेकर मुखर सशस्त्र विद्रोही संगठन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 86 जवानों को मार गिराने का दावा किया है। बीएलए ने कहा कि सेना के कई रडार नष्ट कर दिए हैं। सैन्य काफिले, हवाई अड्डा और मौत के दस्ते पर हमले कर सुरक्षा बलों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया गया। द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक्स पर वीडियो जारी किया है। यह वीडियो 14 मिनट का है। इस वीडियो में रडार प्रणालियों का विनाश, शम्सी एयरबेस पर रॉकेट से हमला, झाल मगसी पर हमले, सोराब और कुर्दगाप में सैन्य काफिलों पर हमले और कदन और मस्तुंग में सैन्य शिविरों पर हमले दिखाए गए हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि बीएलए ने दलबांदिन में खनन स्थल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। पंजगुर में पाकिस्तान सरकार समर्थित समूह मौत का दस्ता के मुख्यालय पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया गया है।

वीडियो में पाकिस्तान की सेना के सैन्य वाहनों, हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों को जलाते हुए दिखाया गया है। बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलोच ने आज विस्तृत बयान जारी कर कहा है कि लड़ाकों ने 29 मार्च को कब्जे वाले बलोचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ समन्वित हमले शुरू किए। यह हमले एक अप्रैल तक जारी रहे। पंजगुर, शापक, बसिमा, साबी, नसीराबाद, डेरा बुगती, मस्तंग, क्वेटा, नुश्की, ज़मरान, दश्त, सोराब, झाल मगसी, दलबंदिन, खारान, वाशक और कलात में कुल 65 हमले किए गए। इन हमलों में 86 से अधिक कर्मी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।

प्रवक्ता ने कहा कि इन हमलों में सेना के शिविरों सहित हवाई अड्डों, रडार प्रणालियों, संचार टावरों, रेलवे ट्रैक, पुलों और गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया। पंजगुर और ज़मरान में हुई झड़पों में बीएलए के छह लड़ाकों की मौत हो गई।

'हिंदी थोपने' के एमके स्टालिन के आरोप निराधार: प्रधान

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर लगाए गए 'हिंदी थोपने' के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह राजनीतिक विफलताओं को छिपाने का प्रयास है। प्रधान ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषाई स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीति को 'अनिवार्य हिंदी' के रूप में पेश कर युवाओं के बहुभाषी बनने के अवसरों को बाधित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बहुभाषावाद किसी भाषा को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। केंद्र सरकार सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं एवं ढांचों के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पीएम-श्री स्कूलों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि पहले सहमति दी गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद नवोदय विद्यालयों की स्थापना में भी बाधाएं डाली जा रही हैं, जिससे गरीब और वंचित छात्रों को नुकसान हो रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन राज्य सरकार की राजनीति के कारण प्रगति बाधित हो रही है। उन्होंने 'हिंदी थोपने' के मुद्दे को भ्रामक बताते हुए इसे अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया।

इससे पहले स्टालिन ने एक्स पर आरोप लगाया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया पाठ्यक्रम ढांचा हिंदी को बढ़ावा देने और गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर थोपने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि तीन-भाषा फार्मूला वास्तव में हिंदी को दक्षिण भारत में लागू करने का माध्यम बन रहा है। स्टालिन ने सवाल उठाया कि क्या हिंदी भाषी राज्यों में तमिल, तेलुगु या अन्य भारतीय भाषाओं को अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने इसे एकतरफा और भेदभावपूर्ण नीति करार देते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे और भाषाई विविधता के खिलाफ है।

मालदा में ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास दिखा ड्रोन, जांच के निर्देश

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास शनिवार दोपहर एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं।

यह घटना मालदा जिले के मालतीपुर में उस समय हुई जब ममता बनर्जी अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रही थीं। शनिवार को उनकी यह दूसरी जनसभा थी। इससे पहले उन्होंने मानिकचक में सभा की थी और इसके बाद उन्हें गाजोल में तीसरी जनसभा के लिए जाना था। जैसे ही वह हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ीं, उसी दौरान एक ड्रोन उसके सामने मंडराता हुआ दिखाई दिया। इसे देखते ही मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए रुक गईं और मंच से ही पुलिस को मामले पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पुलिस को सतर्क रहना चाहिए और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह ड्रोन कहां से आया और प्रतिबंधित वायु क्षेत्र में कैसे पहुंच गया। प्रशासन ने अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उल्लेखनीय है कि, हाल के दिनों में मुख्यमंत्री की हवाई यात्राओं के दौरान कुछ अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। 26 मार्च को खराब मौसम के कारण उनका विमान समय पर कोलकाता हवाई अड्डे पर उतर नहीं पाया था और लगभग 70 मिनट तक शहर के ऊपर चक्कर लगाता रहा था। इस दौरान बेहाला उड्डयन क्लब में उतरने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन अंततः विमान को दमदम हवाई अड्डे पर उतारा गया।

नेपाल के पोखरा में फेवाताल के पास अवैध निर्माण पर चला डोजर, बालेन्द्र शाह के निर्देश पर कार्रवाई

एजेंसी, काठमांडू

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के निर्देश पर पर्यटकीय शहर पोखरा में फेवाताल के आसपास बनाए गए अवैध टहरों (अस्थायी ढांचों) को पोखरा महानगरपालिका ने हटाना शुरू कर दिया है। पोखरा के मेयर धनराज आचार्य ने बताया कि बीती मध्यरात प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का फोन पर निर्देश मिलने पर महानगरपालिका ने शनिवार सुबह से डोजर चलाकर फेवाताल किनारे बने ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है।

महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापा के अनुसार, अब तक 32 टहरों को डोजर की मदद से गिराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नेपाल पुलिस के सहयोग से की जा रही है। इससे पहले नवगठित संघीय सरकार ने फेवाताल क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को तीन महीने के भीतर हटाने का निर्णय लिया था। मंत्रिपरिषद की 100-सूत्रीय कार्ययोजना में भी इस मुद्दे को शामिल किया गया था।

कार्रवाई के दौरान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य के स्वामित्व वाले होटल वॉटरफ्रंट में भी डोजर चलाया गया। इस दौरान होटल का स्विमिंग पूल और गेट सहित कई संरचनाएं तोड़ी गईं। कास्की जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी हरि बहादुर बस्नेत के अनुसार, इस अभियान में जिला पुलिस, बैदाम पुलिस कार्यालय, महानगर प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के करीब 150 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस कार्रवाई पर कुछ स्थानीय निवासियों ने असंतोष भी व्यक्त किया है।

ईरानी कच्चे तेल के कार्गो के चीन डायवर्ट किए जाने की खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत: सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने ईरानी कच्चे तेल के एक कार्गो को पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों के कारण गुजरात के वाडिनार से चीन की ओर मोड़ दिए जाने की खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत एवं भ्रामक बताते हुए खारिज किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पोस्ट में उन हालिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों के कारण ईरान से आने वाले कच्चे तेल की एक खेप को भारत के बजाय चीन भेज दिया गया था। मंत्रालय ने इन दावों को "तथ्यात्मक रूप से गलत" बताया और भरोसा दिलाया कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है।

मंत्रालय ने बताया, "ईरानी कच्चे तेल के एक कार्गो को 'पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों' के कारण भारत के वाडिनार से चीन की ओर मोड़े जाने की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।" मंत्रालय ने कहा कि ईरान में चल रहे युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में पैदा हुई रुकावटों के बावजूद भारतीय रिफाइनरों ने ईरान से होने वाली सप्लाई समेत अपनी कच्चे तेल की जरूरतें पहले ही पूरी कर ली हैं।

कच्चे तेल के व्यापार में जहाजों का मार्ग बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। समुद्र में जा रहे कार्गो अक्सर व्यापार अनुकूलन और परिचालन लचीलेपन के आधार पर बीच यात्रा में अपना गंतव्य बदल लेते हैं। मंत्रालय ने बताया कि ईरान में चल रहे युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में पैदा हुई बाधाओं के बावजूद भारतीय रिफाइनरों ने अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतें पहले ही पूरी कर ली हैं, जिसमें ईरान से होने वाली आपूर्ति भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि ईरानी कच्चे तेल के आयात में पेमेंट को लेकर कोई रुकावट नहीं है, जैसा कि अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत 40 से ज़्यादा देशों से कच्चा तेल लेता है और कंपनियों के पास कमर्शियल ज़रूरतों के हिसाब से सोर्सिंग में बदलाव करने की पूरी आजादी है।

पेट्रोलियम मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इस हफ्ते की शुरुआत में आई उन रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित टैंकर 'पिंग शुन', जो ईरानी कच्चा तेल ले जा रहा था, इसने पहले भारत के वडीनार बंदरगाह को अपना गंतव्य बताया था, लेकिन बाद में चीन की ओर अपना रास्ता बदल लिया।

इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की सप्लाई से जुड़ी चिंताओं पर भी बात की और कुछ दावों को गलत बताया।

फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026 (एफसीआरए 2026)- पारदर्शिता और जवाबदेही बनाम नियंत्रण और दमन की नीति- उद्देश्य,विवाद और संसद में गतिरोध का गहन विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026: संप्रभुता, सिविल सोसाइटी और लोकतंत्र के बीच संतुलन का संघर्ष

» फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026- भारत के लोकतांत्रिक चरित्र,राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक पहचान के बीच एक गहरे वैचारिक संघर्ष का प्रतीक -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत में विदेशी धन के प्रवाह और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला कानूनफॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) लंबे समय से राजनीतिक,सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय बहस का केंद्र रहा है। वर्ष 2026 में प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026 ने इस बहस को और तीखा बना दिया है। एक ओर सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और संप्रभुता की रक्षा के लिए मास्टरस्ट्रोक बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और सिविल सोसाइटी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार मान रहे हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क्रि यह केवल एक कानूनी संशोधन नहीं,बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे,राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक संबंधों को प्रभावित करने वाला व्यापक मुद्दा बन गया है।भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में गैर- सरकारी संगठन (एनजीओ),ट्रस्ट और सिविल सोसाइटी संस्थाएं सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इन संगठनों को अक्सर विदेशी स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने कार्यक्रमों और अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026 (एफसीआरए 2026) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधायी पहल के रूप में उभरा है। इस बिल का घोषित उद्देश्य विदेशी फंडिंग को नियंत्रित कर पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, लेकिन इसके प्रावधानों और संभावित प्रभावों को लेकर विपक्ष और सिविल सोसाइटी में व्यापक असहमति देखी जा रही है। एफसीआरए कानून का मूल उद्देश्य विदेशी धन के प्रवाह को विनियमित करना है ताकि इसका उपयोग भारत की संप्रभुता,अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ न हो।यह कानून पहली बार 1976 में लागू किया गया था और बाद में 2010 में इसे व्यापक रूप से संशोधित किया गया। 2020 में भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिनमें प्रशासनिक खर्च की सीमा, सब-ग्रांटिंग पर रोक और आधार आधारित पहचान जैसे प्रावधान शामिल थे। 2026 का प्रस्तावित संशोधन इसी श्रृंखला का अगला चरण माना जा रहा है, जिसमें सरकार और अधिक सख्ती लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि कुछ एनजीओ विदेशी फंडिंग का उपयोग ऐसे कार्यों में कर रहे हैं जो न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं,बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, सरकार का दावा है कि विदेशी धन का उपयोग अवैध धर्मांतरण, अलगाववादी गतिविधियों और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए किया गया है। इसलिए,एफसीआरए 2026 का मुख्य उद्देश्य इन खतरों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी सहायता का उपयोग केवल वैध और पारदर्शी उद्देश्यों के लिए ही हो।सरकार के अनुसार, यह बिल डीप स्टेट जैसी अवधारणाओं को खत्म करने की दिशा में एक कदम है जहाँ गैर-सरकारी संस्थाएँ विदेशी प्रभाव के जरिए नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, यह तर्क दिया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग का उपयोग कभी-कभी सामाजिक अशांति,विरोध आंदोलनों या राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए कड़े नियंत्रण जरूरी हैं। साथियों बात अगर हम इस बिल के प्रमुख प्रावधानों को समझने की करें तो इसमें विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए कड़े पंजीकरण और निगरानी तंत्र को लागू करना शामिल है।सरकार ने यह भी प्रस्तावित किया है कि यदि किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो जाता है या वह स्वयं सरेंडर करता है,तो उसके द्वारा विदेशी फंड से निर्मित संपत्तियों को सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण के अधीन ले लिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी संपत्तियां निजी लाभ या संदिग्ध गतिविधियों के लिए उपयोग न हों, बल्कि उन्हें सार्वजनिक हित में उपयोग किया जा सके।इसके अतिरिक्त, बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठन नीतिगत मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में नीति निर्माण का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए और बाहरी वित्तपोषण से प्रभावित संस्थाओं को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।हालांकि, इन प्रावधानों को लेकर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उनका आरोप है कि यह बिल सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे वह असहमति की आवाजों को दबा सकती है। विपक्ष का कहना है कि नीतिगत हस्तक्षेप की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे सरकार किसी भी संगठन को मनमाने ढंग से निशाना बना सकती है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और मानवाधिकार संगठनों को लेकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि वे इस कानून के तहत सबसे अधिक प्रभावित होंगे। साथियों बात अगर हम इस बिल के संशोधन पर विपक्ष वह समाज के तर्क को समझने की करें तो पूरे विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है।उनका कहना है कि यह कानून सरकार को अत्यधिक शक्तियाँ देता है,जिससे वह असहमति की आवाज़ों को दबा सकती है।एनजीओ,मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा सकता है।विपक्ष का यह भी आरोप है कि राष्ट्रीय हित जैसी अस्पष्ट परिभाषा का दुरुपयोग कर सरकार आलोचनात्मक संगठनों को बंद कर सकती है।इसके अलावा, आधार अनिवार्यता और निगरानी प्रणाली को निजता के अधिकार के खिलाफ बताया जा रहा है।लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताते हुए नारेबाजी की और वॉकआउट किया।संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने के अधिकार पर यह बिल प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यदि किसी संगठन को केवल इस आधार पर प्रतिबंधित किया जाता है कि वह सरकारी नीतियों की आलोचना कर रहा है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाया है कि क्या सरकार पारदर्शिता के नाम पर सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता को सीमित कर रही है।केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस बिल को लेकर विशेष रूप से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। केरल में, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एनजीओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बिल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक बहस छिड़ गई है। राज्य सरकार और विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून राज्य के विकास कार्यों को प्रभावित कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बाधित कर सकता है।संसद में इस बिल को लेकर जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, वह केवल राजनीतिक असहमति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह गहरे वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाता है। विपक्ष ने इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की, ताकि इसके प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा की जा सके। उनका मानना था कि इतने महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाले कानून को जल्दबाजी में पारित करना उचित नहीं होगा।सरकार हालांकि इस बिल को राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक बताते हुए इसे शीघ्र पारित करने के पक्ष में थी। लेकिन विपक्ष के विरोध, संसद में हंगामे और सहमति के अभाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। यह स्थगन इस बात का संकेत है कि सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर अभी भी सटीक रूप से सहमति नहीं बन पाई है। साथियों बात अगर हम इस संशोधन बिल से सिविल सोसाइटी पर प्रभावः नियंत्रण या सुधार? इसको समझने की करें तोभारत में सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या मानवाधिकार का क्षेत्र हो।इस बिल के बाद, छोटे और मध्यम एनजीओ के लिए विदेशी फंड प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इससे उनकी गतिविधियाँ सीमित हो सकती हैं।हालांकि, सरकार का तर्क है कि इससे केवल फर्जी या संदिग्ध संगठनों पर असर पड़ेगा, जबकि वास्तविक काम करने वाले संगठनों को कोई समस्या नहीं होगी।यह बहस इस मूल प्रश्न पर आकर टिकती है—क्या नियंत्रण पारदर्शिता लाता है या स्वतंत्रता को सीमित करता है? साथियों बात अगर हम इस बिल को अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष में समझने की करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भी इस बिल को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।कई वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और विदेशी सरकारों ने चिंता व्यक्त की है कि भारत में सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे कानून लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश का आंतरिक मामला है और हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करने का अधिकार है।इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पारदर्शिता और सुरक्षा के नाम पर सख्ती जरूरी है, या फिर इससे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न केवल विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोका जाए, बल्कि सिविल सोसाइटी की भूमिका और स्वतंत्रता को भी संरक्षित किया जाए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि एफसीआरए 2026 केवल एक विधायी प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे,नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की एक जटिल चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में इसका स्थगन यह दर्शाता है कि इस विषय पर व्यापक सहमति और गहन विचार- विमर्श की आवश्यकता है।आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर किस प्रकार का समाधान निकालते हैं और क्या यह कानून वास्तव में अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा कर पाता है या नहीं।

-संकलनकर्ता लेखक - क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

क्षितिज के पारः लहरों पर लिखती भारत की नई शौर्यगाथा

लेखक- दिलीप कुमार पाठक

उफनती लहरें, गहरा नीला समंदर और क्षितिज पर डूबता सूरज—ये दृश्य अक्सर हमें सुकून देते हैं, लेकिन इसी असीम विस्तार के पीछे छिपी है एक राष्ट्र के स्वाभिमान और समृद्धि की वह कहानी, जिसे हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में याद करते हैं। यह दिन केवल एक तारीख भर नहीं है, बल्कि यह उस साहस का उत्सव है जिसने सदियों पहले विदेशी बेड़ियों को तोड़कर खुले समुद्र में अपनी पहचान दर्ज की थी। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब समंदर पर केवल फिरंगियों का राज हुआ करता था। उनके जहाज चलते थे, उनके नियम चलते थे और हमारी अपनी विरासत कहीं किनारे पर खड़ी असहाय नजर आती थी। ऐसे में एक हिंदुस्तानी जहाज, एसएस लॉयल्टी, मुंबई के तट से लंदन के लिए निकलता है। वह सिर्फ लकड़ी और लोहे का ढांचा नहीं था, वह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का वह पुल था जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाएं केवल जमीन तक सीमित नहीं हैं। वह यात्रा एक विद्रोह थी, एक घोषणा थी कि अब हम लहरों के साथ बहेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी दिशा में मोड़ेंगे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वह एक छोटी सी शुरुआत आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुकी है। भारत की करीब साढ़े सात हजार किलोमीटर लंबी तटरेखा केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। हमारे बंदरगाह आज केवल सामान उतारने और चढ़ाने की जगह नहीं रह गए, वे आधुनिक भारत के वे द्वार बन चुके हैं जहाँ से आत्मनिर्भर भारत का सपना दुनिया के बाजारों तक पहुँच रहा है। देश का लगभग 95% व्यापार आज भी इन्हीं लहरों के रास्ते होता है। ज़रा सोचिए, उन गुमनाम नाविकों के बारे में जो महीनों तक अपनों से दूर, अनजानी हवाओं और तूफानी लहरों के बीच डटे रहते हैं ताकि हमारे घरों के चिराग जलते रहें और कारखानों के पहिए घूमते रहें। उनका त्याग इस समुद्री प्रगति का असली आधार है। अक्सर हम हिमालय की ऊंचाइयों की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन दक्षिण में फैले इस विशाल रत्नगर्भा नीले समंदर की गहराई को भूल जाते हैं। आज भारत जिस नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहा है, वह भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। गहरे समुद्र से निकलने वाले खनिज हों या तटों पर बसते मछुआरे भाइयों का जीवन, हर एक बिंदु इस विशाल तस्वीर का हिस्सा है। आधुनिक तकनीक ने अब हमें वह सामर्थ्य दे दिया है कि हम समंदर से न केवल संपदा निकाल रहे हैं, बल्कि उसकी रक्षा करना भी सीख रहे हैं। प्लास्टिक के प्रदूषण से लेकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तक, आज का भारत एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति बनकर उभर रहा है। आज हम केवल व्यापारिक जहाज ही नहीं चला रहे, बल्कि समंदर की लहरों पर अपना स्वदेशी आईएनएस विक्रांत जैसा विमानवाहक पोत भी लहरा रहे हैं। यह उस तकनीकी कौशल का प्रमाण है जो बताता है कि हम रक्षा और सुरक्षा के मामले में भी अब किसी के मोहताज नहीं हैं। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती धमक यह सुनिश्चित करती है कि यह क्षेत्र शांति और प्रगति का केंद्र बना रहे। सागर का जो विजन हमारे विज़नरी लोगों ने दिया है, वह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सुरक्षा और विकास का मंत्र है। जैसे-जैसे दुनिया सिमट रही है और व्यापार के नए गलियारे खुल रहे हैं, समुद्र का महत्व और बढ़ता जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी को अब इन लहरों में छिपे करियर और एडवेंचर को पहचानना होगा। यह केवल जहाजों का संचालन नहीं है, यह वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था की वह धुरी है जहाँ भारत अब अगली कतार में खड़ा है। जब तक सूरज की किरणें इन लहरों पर चमकती रहेंगी, भारत की यह समुद्री यात्रा निरंतर चलती रहेगी। आज का दिन रुककर उन लहरों को सलाम करने का है, जिन्होंने हमें दुनिया से जोड़ा। उन पूर्वजों को नमन करने का है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस नहीं खोया। और सबसे बढ़कर, उन युवाओं को प्रोत्साहित करने का है जो आने वाले समय में भारत की इस गौरवगाथा को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समुद्र हमें सिखाता है कि शांत रहकर भी विशाल कैसे बना जाता है और चुनौतियों के थपेड़ों को सहकर भी अपनी मंजिल कैसे पाई जाती है।

पश्चिम बंगाल बढ़ती अराजकताः लोकतंत्र के लिए चुनौती

लेखक - ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है।

अफगानिस्तान से लेकर भारत तक भूकंप के झटके!

लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन

भारत मे दिल्ली-एनसीआर सहित समूचे उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के आने पर लोग घरों से बाहर निकल गए। ये झटके दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा राजस्थानऔर पंजाब सहित कई प्रदेशों में महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है।दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होने से लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि भूकंप से कहीं जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है।भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है। भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, पुंछ और कश्मीर घाटी के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं।भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में जमीन के अंदर 175 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का केंद्र जमीन के काफी अंदर होने की वजह से इसका असर कम हुआ है। अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सहित उत्तर भारत में भूंकप आने से पहले तिब्बत में धरती हिली थी। तिब्बत में बीती रात करीब 8.12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तिब्बत में आए भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई थी। पिछले साल म्यांमार और थाईलैंड में दोपहर के समय आए भयंकर भूकंप को रिक्टर पैमान पर 7.9 की तीव्रता का नापा गया था। इतने तेज भूकंप के कारण दोनों ही देशों में भारी तबाही हुई थी। इन देशों की विशाल इमारतें और पुल ढह गए और भारी जान माल का नुकसान हुआ था।थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने बैंकाक के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार बताया गया था। जिसका भारी प्रभाव थाईलैंड तक पड़ा था। बैंकॉक में 7.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से इमारतें हिलने लगीं थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के जीएफजेड भूविज्ञान केंद्र ने बताया कि दोपहर को यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिसका केंद्र म्यांमार में था। ग्रेटर बैंकॉक क्षेत्र की आबादी 170 लाख से अधिक है, जिनमें से कई लोग ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में रहते हैं।दोपहर करीब डेढ़ बजे भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घनी आबादी वाले मध्य बैंकॉक की ऊंची इमारतों एवं होटल से लोगों को बाहर निकाला गया। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ ऊंची इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में 'स्वीमिंग पूल' में पानी में लहरें उठती दिखीं। भूकंप का केंद्र मध्य म्यांमार में था, जो मोनीवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है।थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जहां सैंकड़ो लोग इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बताया कि म्यांमार में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मंडाले शहर के पास 10 किमी की गहराई पर था। म्यांमार दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड राज्यों में आज आए भूकंप से लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। वही दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में विगत वर्ष 17 फ़रवरी की सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे,जिसमे कई सेकंड तक धरती डोलती रही थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई थी, इसका केंद्र दिल्ली के पास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था। इसीलिए तेज झटके महसूस हुए। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। भूकंप सुबह 5 बजकर 36 मिनट पर आया था, जिससे लोगों की नींद उड़ गई थी।भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते है, जिससे यहां मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा रहता है। समय-समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, लेकिन इस तीव्रता के झटके बहुत समय बाद महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड समेत नेपाल और भारत के अन्य क्षेत्रों में धरती बार बार डोलने लगती है। भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ जाते है।सन 2022 में आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि गहरी नींद में सोए लोग हड़बड़ाहट में उठे और घरों से बाहर की ओर भागे थे।उस समय उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई थी। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गुरुग्राम में भी कई सेकेंड तक भीषण झटके महसूस किए गए। इसके कारण लोग उठ गए और कई लोग अपनी सोसायटी में बाहर निकल आए।ऐसा लगा कि बेड को कोई बहुत तेज धक्का मार रहा है। इस दौरान घर के फैन और झूमर भी भूकंप के असर के कारण तेजी से हिलने लगे।भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमण्डल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकम्पीय तरंगों की वजह से होता है। भूकम्प बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुँचाने से लेकर पूरी आबादी को ध्वस्त कर सकने की इसमें क्षमता होती है।

युवराज बोले- धोनी के सच्चाई बताने के बाद लिया रिटायरमेंट

कप्तान विराट, कोच ने स्पष्ट नहीं किया था कि आगे टीम में लेंगे या नहीं

मुंबई (एजेंसी)। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी से पता चला था कि अब चयनकर्ता उनके नाम पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ही युवराज ने 10 जून 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। स्पोर्ट्स तक से बातचीत में युवराज ने कहा कि 36–37 साल की उम्र में जब वे टीम से अंदर–बाहर हो रहे थे, तब न तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए), न ही कप्तान विराट कोहली और न ही कोच रवि शास्त्री ने उनसे सीधे बात की। युवी ने कहा, उस समय मुझे लगा कि मैं बीच में फंस गया हूं। मैंने देश के लिए इतना क्रिकेट खेला, तो कम से कम थोड़ी इज्जत और साफ बात तो बनती थी, लेकिन मुझे कुछ भी साफ नहीं बताया गया।

धोनी ने फोन पर बताया था सच

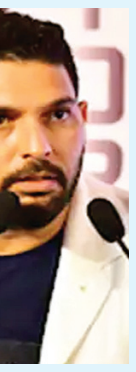

युवराज ने कहा कि उन्हें कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को फोन किया। धोनी उस समय कप्तान नहीं थे, लेकिन वे पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। युवराज के मुताबिक, धोनी ने मुझे सही नजरिया दिया। उन्होंने साफ कहा कि सिलेक्टर्स अब आगे की तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी योजनाओं का हिस्सा नहीं हूं। धोनी की इस बात ने मुझे वह स्पष्टता दी जो मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा था।

फिटनेस के नाम पर रिटायरमेंट के लिए दबाव बनाया गया– युवराज ने यह भी आरोप लगाया कि मैनेजमेंट ने उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। उनसे कहा गया था कि वे अब फिटनेस टेस्ट (यो–यो टेस्ट) पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें खेल को अलविदा कह देना चाहिए। इस पर उन्होंने साफ जवाब दिया कि रिटायर होना उनका फैसला होगा, जबकि टीम में खिलाना या नहीं खिलाना मैनेजमेंट का निर्णय है। युवराज पर्सनल टिप्पणियों के चलते कमेंट्री से दूरी बनाए हुए हैं युवराज ने यह भी बताया कि वे अब तक कमेंट्री से दूर क्यों रहे। उन्होंने साफ कहा कि वे उन लोगों के साथ बैठकर काम नहीं करना चाहते, जिन्होंने उनके बारे में निजी (पर्सनल) टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा, अब जब मैं रिटायर हो चुका हूं, तो इस बारे में खुलकर बोल सकता हूं।

फ़ीडे कैंडिडेट शतरंज

सिंदारोव नें नाकामुरा को हारकर लगाई जीत की हैट्रिक

साइप्रस (एजेंसी)। फ़ीडे कैंडिडेट शतरंज में उज़्बकेले एक अंक किस्तान के विश्व कप विजेता जावोखीर सिंदारोव नें जीत की हैट्रिक लगाते हुए खुद को बाक़ी सभी खिलाड़ियों के मुक़ाबले सबसे आगे बनाये रखा है । पिछले तीन राउंड में उन्हों क्रमश : खिताब के तीन प्रबल दावेदार भारत के आर प्रज्ञानन्दा , यूएसए के फैबियानो कारुआना और अब हिकारू नाकामुरा को मात देते हुए 4.5 अंकों के साथ ख़ुद को खिताब की दौड़ में बेहद मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया है हालांकि अभी 9 राउंड और खेले जाने बाक़ी है पर पूर्व विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव जैसे खिलाड़ी भी सिंदारोव के इस प्रदर्शन से बेहद प्रभावित नज़र आ रहे है और उन्हें कैंडिडेट जीतने का बड़ा दावेदार मान रहे है ।

अन्य बाज़ियों में आज फैबियानो कारुआना नें पिछली हार से वापसी करते हुए जर्मनी के मैथियास ब्लूबम को पराजित कर दिया ।

पंजाब ने टी-20 में भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

● 9वीं बार 200+ चेज किए, चेन्नई ने आईपीएल में 36वीं बार 200 रन बनाए, यह बने रिकॉर्ड्स

चेन्नई (एजेंसी)। आईपीएल के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेपॉक में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट पर 208 रन बनाए। टीम के लिए आयुष म्हात्रे ने 73 रन की पारी खेली, हालांकि उन्हें दो बार जीवनदान भी मिला। जवाब में पंजाब ने 18.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ पंजाब ने टी-20 क्रिकेट में भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9वीं बार 200+ रनचेज किया। वहीं चेन्नई ने इस मैच में 36वीं बार 200+ स्कोर बनाया।

पंजाब ने 9वीं बार 200+ रनचेज किया– पंजाब किंग्स ने टी-20 क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम ने 200+ रनचेज के मामले में 9वीं जीत दर्ज की। इससे पहले भारत की टीम ने 8 बार 200+ रनचेज किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 7 और मुंबई इंडियंस ने 6 बार यह कारनामा किया है।

पंजाब किंग्स का दूसरा सबसे बड़ा रनचेज

पंजाब किंग्स ने अपना दूसरा सबसे बड़ा रनचेज किया। टीम ने 210 रन का टारगेट 18.4 ओवर में हासिल किया। टीम का सबसे बड़ा रनचेज 262 रन का है। इसे पंजाब ने 2024 में ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हासिल किया था।

चेन्नई ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर बनाए– चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर बनाने वाली टीम बन गई। टीम ने अब तक 36 बार 200 का आंकड़ा पार किया है। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 35 बार इस स्कोर तक पहुंची है।

संजू ने फिर मायूस किया– दूसरे ओवर में चेन्नई का पहला विकेट गिरा। ओवर की छठी गेंद जेवियर बार्टलेट ने ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। संजू सैमसन ड्राइव खेलने के लिए पीछे हटे, लेकिन गेंद की मूवमेंट को कवर नहीं कर सके और बल्ले का हल्का किनारा लग गया। गेंद सीधे विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के पास गई, जिन्होंने आसान कैच लपक लिया। संजू 7 रन बनाकर आउट हुए।

सरफराज ने अर्शदीप पर हैट्रिक चौके लगाए

14वें ओवर में सरफराज खान ने अर्शदीप सिंह पर लगातार तीन चौके जड़ दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर सरफराज ने आगे बढ़कर जगह बनाई और मिड–ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर अर्शदीप ने शॉर्ट लेंथ डाली। सरफराज ने शॉट खेला और गेंद को विकेटकीपर के ऊपर से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। फिर चौथी गेंद पर सरफराज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को लेट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया और चौका पूरा किया।

प्रशांत वीर ने डेब्यू पर चौके से खाता खोला

चेन्नई सुपर किंग्स के अनकैप्ड ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने इस मैच से आईपीएल डेब्यू किया। टीम ने उन्हें मेगा ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन ने ऑफ स्टंप के आसपास शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। प्रशांत ने शॉट खेला। गेंद तेजी से आई और ग्लव्स का हल्का किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा में निकल गई। इसी चौके के साथ प्रशांत ने आईपीएल में अपना खाता खोला।

प्रियांश ने बाउंड्री से पहले रन बनाए

पंजाब की पारी की शुरुआत प्रियांश आर्या ने लगातार दो बाउंड्री से की। ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद ने इनस्विंगर डाली। प्रियांश ने सीधे बल्ले से नॉन–स्ट्राइकर के पास से चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर खलील ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। प्रियांश ने जल्दी से लेंथ पहचानी, घूमकर पुल शॉट खेला और गेंद को मिड–विकेट के ऊपर से सिक्स के लिए भेज दिया।

स्लो ओवर के लिए अय्यर पर 24 लाख का जुर्माना

● अब एक और गलती की तो पंजाब के कप्तान पर लगेगा एक मैच का बैन

चेन्नई (एजेंसी)। आईपीएल के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, लेकिन इस मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर पर 24 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

यह इस सीजन का पंजाब किंग्स का दूसरा ओवर-रेट अपराध है। इसलिए सिर्फ कप्तान ही नहीं, पूरी प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर को भी सजा मिली है। बाकी सभी खिलाड़ियों पर ?6 लाख या उनके मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया गया है। पंजाब किंग्स के सभी खिलाड़ियों पर ?6 लाख या उनके मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया गया है।

अगली बार बैन तय

आईपीएल के नियमों के मुताबिक, अगर अब टीम से फिर ऐसी गलती होती है तो अय्यर पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और एक मैच का बैन भी झेलना पड़ेगा। पंजाब को अभी लीग स्टेज में 12 से ज्यादा मैच खेलने हैं, ऐसे में अब गलती की गुंजाइश बहुत कम बची है।

श्रेयस अय्यर ने 50 रन बनाए– इस मैच में श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी से टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने 29 गेंदों पर 50 रन की शानदार पारी खेली। उनकी नेहल वाधेरा के साथ 59 रन की साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पंजाब किंग्स को जीत के लिए 209 रन का टारगेट मिला था, जिसे उन्होंने 5 विकेट खोकर आराम से हासिल कर लिया।

आयुष म्हात्रे की पारी पर भारी पड़ी पंजाब की बैटिंग

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 209 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। चेन्नई की ओर से युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने 43 गेंदों में 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (28 रन) के साथ 96 रनों की साझेदारी की। हालांकि, पंजाब की शुरुआत भी प्रियांश आर्य की 11 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी से हुई। अंत में प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली और अय्यर की पारियों ने चेन्नई के स्कोर को छोटा साबित कर दिया और पंजाब ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

विराट कोहली का विकेट लेना चाहता है पंजाब किंग्स का ये गेंदबाज

नईदिल्ली (एजेंसी)। पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज वेन ड्वार्शुइस ने आईपीएल 2026 में डेब्यू से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस सीजन में खेलने का मौका मिलता है तो वह सबसे ज्यादा विराट कोहली का विकेट लेना चाहेंगे। ड्वार्शुइस ने कहा कि कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और उनका विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए खास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे मैच होम ग्राउंड पर हो या बेंगलुरु में, वह कोहली का विकेट लेना चाहेंगे।

4.4 करोड़ में पंजाब ने खरीदा

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने बेन ड्वार्शुइस को 4.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह इससे पहले भी टीम स्क्वॉड का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था। इस बार टीम के हेड कोच रिकी पोंटिग के अंडर उन्हें मौका मिलने की उम्मीद है। टीम में कई विदेशी तेज गेंदबाज होने की वजह से प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान नहीं है।

मिल सकता है मौका

आईपीएल 2026 लीग स्टेज में पंजाब किंग्स और रायल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला 17 मई को धर्मशाला में खेला जाना है। अगर उस मैच में ड्वार्शुइस को मौका मिलता है तो उनकी सीधी टक्कर विराट कोहली से हो सकती है। ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए खास हो सकता है।

आईपीएल में मौके पर क्या बोले ड्वार्शुइस

बेन ड्वार्शुइस ने कहा कि आईपीएल जैसी बड़ी लीग में जब भी खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको लगातार मौके मिलते हैं। लेकिन अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि खुद को साबित कर सकें।

टीम में जगह बनाना आसान नहीं– पंजाब किंग्स की टीम में तेज गेंदबाजों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिसके चलते बेन ड्वार्शुइस को अभी तक मौका नहीं मिला है। टीम के पास कई तेज गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं, इसलिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए उन्हें शानदार प्रदर्शन करना होगा। हालांकि टीम मैनेजमेंट उन्हें सीजन के दौरान मौका दे सकता है, जहां वह खुद को साबित करना चाहेंगे।

व्यापार

टोल प्लाजा पर बंद होगी कैश पेमेंट, नेशनल हाईवेज पर 10 अप्रैल से चलेगा केवल फास्टैग और यूपीआई

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में नेशनल हाईवेज पर पेमेंट का तरीका अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और केवल फास्टैग तथा यूपीआई से ही पेमेंट किया जा सकेगा। इस तरह टोल प्लाजा पर पेमेंट का सिस्टम पूरी तरह डिजिटल मोड में आ जाएगा। एक सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 10 अप्रैल से पूरे देश में नेशनल हाईवे पर केवल डिजिटल टोलिंग सिस्टम की सुविधा होगी। सरकार ने सभी नेशनल हाईवे फीस प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। अब इसे पूरी तरह लागू किया गया है। डिजिटल टोलिंग ईकोसिस्टम बनाने और पूरे नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले ही कहा था कि टोल पेमेंट को केवल डिजिटल तरीकों से प्रोसेस्ड किया जाएगा।

क्या होगा फायदा: प्राधिकरण का कहना है कि इस बदलाव से टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम होगी, पेमेंट में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और लोगों का सफर आसान होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 1,150 से अधिक टोल प्लाजा हैं। एनएचएआई का कहना है कि टोल प्लाजा के पूरी तरह डिजिटल पेमेंट्स पर शिफ्ट होने से ट्रैफिक में आसानी होगी और सफर करने वालों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

यूपी में बढ़ा टोल: इस बीच एनएचएआई और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने टोल के रेट्स में बढ़ोतरी की है। ये रेट्स यूपी में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू होंगी। नेशनल हाईवे पर पैसेंजर कार के लिए टोल 10 फीसदी बढ़ाया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के लिए रेट्स में 1.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर कार और स्ङ्क के लिए इसे 665 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये कर दिया गया है। दोपहिया वाहन से सफर करने वालों को 330 रुपये के बजाय अब 335 रुपये देने होंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार के लिए टोल 10 रुपये बढ़ाकर 295 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 5 रुपये बढ़ाकर 145 रुपये कर दिया गया है।

भारत-पाकिस्तान को एक ही चश्मे से देखता है चीन ! कहां लगा रखा है सबसे ज्यादा पैसा

नई दिल्ली, एजेंसी। चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी प्रगति से दुनिया को चौंकाया है। आज वह अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसने दुनिया भर में निवेश कर रखा है। पिछले 20 साल के आंकड़े देखें तो इस दौरान चीन ने सबसे ज्यादा निवेश अमेरिका में किया है। इस दौरान चीन ने अपने जिगरी यार पाकिस्तान में 16.56 अरब डॉलर का निवेश किया है जबकि भारत में उसका निवेश 17.28 अरब डॉलर का रहा है। चीन की इनवेस्टमेंट लिस्ट में भारत 20वें और पाकिस्तान 23वें नंबर पर है। चाइना ग्लोबल इनवेस्टमेंट ट्रैकर के मुताबिक चीन ने 2005 से 2025 के बीच अमेरिका में सबसे ज्यादा 204.14 अरब डॉलर का निवेश किया। दिलचस्प बात है कि अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। दोनों के बीच कई साल से ट्रेड वॉर चल रहा है। इसके बावजूद चीन की निवेश लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया है जहां चीन का निवेश 108.12 अरब डॉलर है।

एनबीडी बैंक का बिक गया 74 प्रतिशत हिस्सा, आरबीआई ने भी दी मंजूरी, 1 साल में 72 प्रतिशत चढ़ा स्टॉक

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दुबई स्थित एमिरेट्स एनबीडी बैंक को आरबीएल बैंक में 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इससे यह बैंक, विदेशी बैंक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आरबीएल बैंक ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि आरबीआई ने यह मंजूरी एक अप्रैल को दी, जिसकी वैलिडिटी एक वर्ष तक रहेगी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दूसरे सबसे बड़े बैंक एमिरेट्स एनबीडी ने अक्टूबर 2025 में आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,853 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद यह मंजूरी दी गई। मंजूरी पत्र के अनुसार, एमिरेट्स एनबीडी (ईएनबीडी) को आरबीएल बैंक की चुकता पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखना होगा। इसके बाद बैंक को सब्सिडी मॉडल के तहत विदेशी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें निवेशक, मूल विदेशी बैंक होगा। आरबीआई ने कहा कि ऐसे बैंक पर पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी मॉडल के तहत संचालित विदेशी बैंकों के लिए नियत प्रावधान लागू होंगे। हालांकि निदेशक मंडल बैठकों में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने की शर्त इस पर लागू नहीं होगी। बैंक को अपने 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' में आवश्यक संशोधन कर आरबीआई से मंजूरी लेने को कहा गया है और बैंक इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा।

41 वाले शेयर में 47 प्रतिशत से ज्यादा उछाल का अनुमान

2 दिग्गज ब्रोकरेज ने कहा-खरीदो

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी सैगिलिटी इंडिया के शेयर भले ही अभी सुस्त हों लेकिन इसमें बढ़त की संभावना है। यह अनुमान दो बड़े ब्रोकरेज का है। एक ब्रोकरेज नोमुरा है तो दूसरा मोतीलाल ओसवाल है। इन दोनों ब्रोकरेज ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। आइए जानते हैं शेयर की वर्तमान कीमत और टारगेट प्राइस। ब्रोकरेज नोमुरा ने कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए उसे बाय रेटिंग दी है और उसका टारगेट प्राइस 55 रुपये तय किया है। यह 47 प्रतिशत से अधिक के रिटर्न मिलने का संकेत दे रहा है। इसके अलावा, मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक के लिए अपनी बाय की सिफ़ारिश दोहराई है और इसका टारगेट प्राइस 58 रुपये तय किया है, जिससे 45 प्रतिशत तक की बढ़त की गुंजाइश बनती है। शेयर की वर्तमान कीमत 41.79 रुपये के स्तर पर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमशः 57.90 रुपये और 35.82 रुपये है।

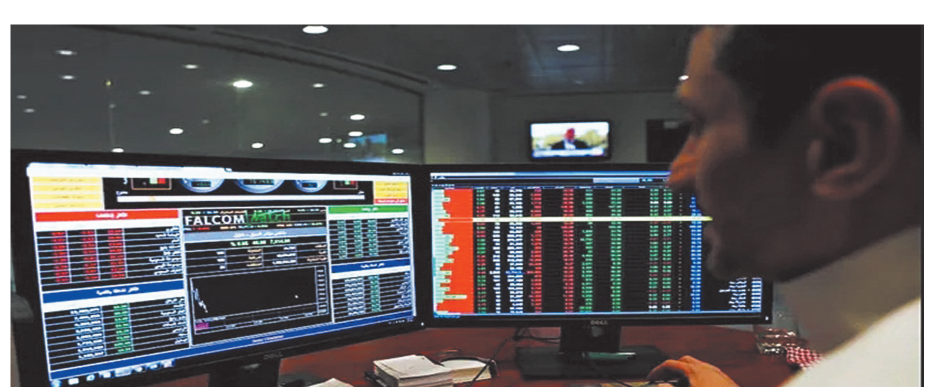

ब्रोकरेज ने क्या कहा: नोमुरा ने इस कंपनी को एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर टेक प्लेयर बताती है, जिसे अपने क्लाइंट्स को लंबे समय तक बनाए रखने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से फायदा मिलता है। रिपोर्ट में अगले दो फाइनेंशियल सालों में प्रति शेयर कमाई में 20 प्रतिशत की मजबूत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी को यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थकेयर पेयर्स के बीच बढ़ते आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स का एक स्ट्रक्चरल बेनेफिशियरी मानती है। ब्रोकरेज का सुझाव है कि हाल ही में किए गए अधिग्रहणों से मिलने वाले तालमेल और बड़े क्लाइंट्स से काम की बढ़ती मात्रा की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में मिड-टीन्स (13-17 प्रतिशत) की दर से बढ़ोतरी जारी रहेगी। घरेलू ब्रोकरेज आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने भी बीते दिनों शेयर को खरीदने की सलाह दी थी। ब्रोकरेज ने कहा था कि शेयर 66 रुपये तक जा सकता है। ब्रोकरेज ने कहा था कि कंपनी ने अपनी पहली एनालिस्ट मीट (25 मार्च, 2026 को) आयोजित की। इसमें यह बात सामने आई कि लगातार विकास का एक मुख्य जरिया बना हुआ है।

कैसे रहे दिसंबर तिमाही के नतीजे: बीते दिनों सैगिलिटी इंडिया ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 23.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 267.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि राजस्व 35.7 प्रतिशत बढ़कर 1,971.1 करोड़ रुपये हो गया। ढ्ढञ्ज सॉल्यूशन प्रोवाइडर देने वाली इस कंपनी का सालाना आधार पर 30.4 प्रतिशत बढ़कर 511 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इस तिमाही में मार्जिन 25.9 प्रतिशत रहा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)